# बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्रं विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि ३ सितम्बर, १९५४ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

---

## तारांकित प्रश्नोत्तर।

## Starred Questions and Answers.

---

### सेक्रेटेरियट पुस्तकालय।

*अ १०३। श्रीमती मनोरमा देवी—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि बहुत पुराना और बहुमूल्य सेक्रेटेरियट पुस्तकालय इन दिनों राजस्व विभाग के सामने बारन्डा में रखा गया है;

(ख) क्या यह बात सही है कि उसमें से बहुत सी बहुमूल्य पुरानी किताबें, कागज आदि प्रतिदिन नष्ट या गायब हो रहे हैं;

(ग) क्या सरकार इसे सिन्हा लाइब्रेरी या किसी अन्य खास सरकारी मकान में रखने का विचार करती है जिससे उसकी हिफाजत हो सके?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(क) यह बात सही है कि सरकारी लाइब्रेरी की कुछ आलमारियां रेवेन्यु डिपार्टमेंट के सामने कोराईडर में रख दी गई हैं चूंकि जगह की कमी थी इसलिए जहां-जहां इसके लिए जगह मिली वहां आलमारी में पुस्तकें रख दी गयी हैं। जो जरूरी किताबें तथा कागजात थे वे अफसरों के कमरे की आलमारी में रख दिये गये हैं।

(ख) जो किताबें अफसरों के कमरे में हैं वे बिलकुल सुरक्षित हैं। लेकिन जो कोराइडर में हैं उनको नुकसान पहुंचने का खतरा है।

(ग) इसके लिए कोई प्रस्ताव सामने नहीं है। यह सेक्रेटेरियेट की लाईब्रेरी है और यह सेक्रेटेरियेट के अफसरों के काम के लिए है। ये किताबें सेक्रेटेरियेट में ही रहनी चाहिए। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को इसके लिए उचित मकान बनाने तथा उसको प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है।

---

अ—शिक्षा विभाग से स्थानान्तरित।

**SPEAKER** : If it is very different from what is mentioned in your notice then also I disallow it on the ground of its being irrelevant.

*Shri **MUNDRIKA SINGH** : On the information of a Sub-Inspector of Police how can you say that the matter is *sub judice*?

**SPEAKER** : The hon'ble member has his own rights under the rules and can take recourse to them in all cases in which he considers that I am unfair to him .

Shri **MUNDRIKA SINGH** : Sir, did the Sub-Inspector of Police inform the Chair that this matter is *sub judice* ?

**SPEAKER** : I am not going to allow any discussion about the Sub-Inspector. I have also received a notice that a member has been arrested. That also shows that the matter is *sub judice*. So I disallow it.

---

उत्तर बिहार की बाढ़ के ऊपर सरकार के वक्तव्य पर वादविवाद ।

**Discussion on the statement of Government on floods in North Bihar.**

श्रीमती रामदुलारी सिंह—अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की समस्या ने एक बार फिर से हमारे देश को डावांडोल कर दिया है। रोजाना सुबह हमें सनसनीखेज खबरें अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं और बाढ़ पीड़ित परिवारों की जुबानी कहानियां सुनकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी हाल ही में लोक सभा में बाढ़ के सिलसिले में जो बहस हुई थी उसमें बताया गया था कि उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप करीब १२ हजार स्क्वायर माइल पर हुआ है और मौत की संख्या केवल ७ है। आज बड़े-बड़े अफसर और मिनिस्टर हवाई जहाज से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी हाल ही में अग्रवाल साहब, किदवई साहब, नन्दा साहब, तथा श्री जगजीवन राम ने हवाई जहाज से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा है कि उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप १५,००० स्क्वायर मील पर हुआ है और करीब ५० करोड़ की क्षति हुई है और नदियों की उबाल के प्रकोप के लपेट में लगभग ८० लाख व्यक्ति आ गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपका अधिक समय मैं नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि सदन के बहुत से सदस्य उस समस्या पर बोलने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन मैं आपसे यह बताना चाहती हूं कि इस बार बाढ़ की जितनी भयंकरता है शायद पहले कभी नहीं हुई थी। बागमती, कोशी और गंडक के लपेट में सैकड़ों गांव पड़ गये हैं। मुजफ्फरपुर के सीतामढ़ी सबडिवीजन में बाढ़ की जो चोट है वह पिछले भूकम्प की चोट से कई गुणा अधिक है। नदियों की बाढ़ एक बार नीचे उत्तर कर फिर ऊंचे चढ़ गयी है जिससे बड़ा नुकसान हुआ है और हो रहा है। इतना ही नहीं कुछ लोगों ने दुबारे फसल बोने की चेष्टा की थी लेकिन वह भी खत्म हो गयी और इस तरह से हम यदि अन्दाज लगावें तो बाढ़ से जो क्षति हुई है वह ५० करोड़ पर नहीं बल्कि ८० करोड़ पर उतरेगी। बाढ़ के सिलसिले में आने वाले संक्रामक रोग, मवेशियों की बीमारी और चारा की समस्या आवागमन की असुविधाएं इत्यादि इन सारी चीजों को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। आज यदि हमारे पास इन क्षतियों को मापने का कोई पैमाना होता तो क्षति करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की आंकी जा सकती थी। मैं बिहार सरकार को धन्यवाद

देना चाहती हूं कि इन अरबों की क्षती की पूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार से साढ़े पांच करोड़ की सहायता की मांग की है।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस संकट काल के समय में एक दूसरे पर दोषारोपण करने से हमारा काम नहीं चलेगा और न उसका समय ही है। मैं दुःख के साथ कहूंगी कि आखिर बाढ़ हर साल आती है और जाती है लेकिन हम बाढ़ के आने पर ही जगते हैं। यहां तक कि नावों का समुचित प्रबन्ध भी नहीं कर पाते। तीन चार साल के अन्दर ही अन्दर चाइना ने बाढ़ की समस्या का समाधान बड़ी खूबी से किया है। हमारे लिए यह शर्म की बात है कि हम ६-७ साल के अन्दर भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सके। खुशी की बात है कि अभी हाल में अग्रवाल साहब ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि "लेट अस फाइट फ्लड्स इन ए चाइनीज वे"।

हमारे किदवई साहब ने भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने भी ऐलान किया है कि बाढ़ क्षेत्र में भूखमरी से एक भी व्यक्ति को मरने नहीं दूंगा और गेहूं का दर उस इलाके में १६ रुपये से कम कर १२ रुपये दर कर दिया है और ५ हजार टन गेहूं बाढ़ क्षेत्र में इसी दर पर पहुंचाने की बात कही है। इसके लिए मैं किदवई साहब को धन्यवाद देना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो प्रमुख समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या यह है कि बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों को किस तरह से सहायता पहुंचाई जा सके और दूसरी यह कि इस बाढ़ के बराबर आने वाले प्रकोप को हम किस तरह समूल नष्ट कर सकें। जहां तक पहली समस्या की बात है, जैसा कल महामाया बाबू ने भी आपको बतलाया था, हमें पार्टी पोलिटिक्स की भावना छोड़कर सभी पार्टियों की सहायता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम दलबन्दी की भावना को छोड़कर सभी दलों के लोगों से मिल-कर काम करें तो समस्या का समाधान आसानी से हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, २, ४ सुझाव आपके माध्यम से मैं सरकार के सामने रखना चाहती हूं। मैं आपसे बताना चाहती हूं कि अभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जमीन्दारों की ओर से रैयतों के खिलाफ तमादी सूट दायर करने की तैयारियां हो रही हैं। मैं सरकार से कहूंगी कि कृपा कर इसके लिए ६ महीने का समय बढ़ा दे ताकि कृषक मुकदमेबाजी की परेशानी से इस संकट के समय में बच जायं। १९४२ में भी ऐसा किया गया था।

दूसरी बात यह है कि अग्रीकल्चरल लोन के अलावे और तरह के कर्ज भी मध्यम वर्ग के लोगों को दिया जाय ताकि वे अपने को इस चोट से संभाल सकें।

सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये १,००० ट्यूब वेल की मंजूरी दी है। लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है कि यदि नौरमल चैनल से जब तक ट्यूब-वेल वहां पहुंचाये जायेंगे तब तक शायद महामारियों की भयंकरता वहां प्रारंभ न हो जाय। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि वह ट्यूब वेल की व्यवस्था बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए जल्द से जल्द करे।

एक सुझाव मैं और आपके सामने रखना चाहती हूं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो स्कूल और कालेज हैं वहां निःशुल्क शिक्षा ७५ प्रतिशत कर दिया जाय।

अलावन की समस्या भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भयंकर रूप लेकर खड़ी है। अतः सस्ते दाम पर कोयला भेजने की व्यवस्था वहां की जाय। उसके बाद मवेशियों के लिए चारा की समस्या है। उसमें मदद पहुंचाने के लिए मेरा सुझाव है कि इस राज्य की जितनी चावल मिलें हैं उन सबों का भूसा और कुंड़ा लेकर

चारा के लिए बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाया जाय। यह सुझाव में सरकार के सामने रखना चाहती हूं कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में ७५ प्रति शत मिट्टी के मकान गिर गये हैं उन्हें शीघ्र बनवाने की व्यवस्था होनी चाहिये और जो अस्थायी मकान बनाने के लिये कम से कम १०,००० टीन के शीट इन इलाकों में भेजे जाने चाहिये। इसके साथ-साथ में चाहूंगी कि सीतामढ़ी सबडिवीजन जो बाढ़ से बिलकुल बरबाद हो गया है उस पर विशेष ध्यान दिया जाय। मैं यह बताना चाहती हूं कि इन सब तमाम चीजों को कुछ हद तक सस्ती हमारी सरकार कर रही है और करने को तैयार भी है। मैं यह मान लेती हूं कि हर बाढ़-ग्रस्त व्यक्ति के पास सहायता पहुंचाने की सरकार की भावना के बावजूद भी अफसरों के अनुभव की कमी के कारण शायद सभी पीड़ित सहायता न प्राप्त कर सकें फिर भी डिस्ट्रीव्यूशन का काम किस तरह से हो, लोगों को किस प्रकार सहायता पहुंचाई जाय ये सारी बातें मेरी समझ से इम्मेटेरियल हैं। असली चीज यह है कि बाढ़ के बार-बार आने वाले प्रकोप को हम किस तरह समूल नष्ट कर सकें, जिससे कहीं न तो ज्यादा पानी रुक सके न कहीं अनावृष्टि का ही सामना करना पड़े। अतः प्रोपर डीस्ट्रीब्युशन ऑफ वाटर के लिये हमें वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना होगा।

ऐसी हालत में बाढ़ के प्रकोप को रोकने के लिये, समूल नष्ट करने के लिये, कोई स्थायी तरीका अख्तियार करना होगा। मैं जानती हूं कि केन्द्रीय सरकार इसके लिये सजग है और कुछ कर रही है। फिर भी बाढ़ को रोकने के लिये वैज्ञानिक तरीका अख्तियार करना होगा। बंगाल, उत्तर बिहार, नेपाल और आसाम में जो योजनाएं चल रही हैं वे चींटी की रफ्तार से चल रही हैं। आज उत्तर बिहार बाढ़ से बरबाद हो गया है। जो उत्तर बिहार सारे उत्तर भारत की फुलवारी समझा जाता था आज बाढ़ से नष्ट हो रहा है। अगर सारे भारत की खाद्य-समस्या को सिर्फ उत्तर बिहार से ही हम पूरा करना चाहते हैं तो हमें वैज्ञानिक तरीका अख्तियार करना होगा। अध्यक्ष महोदय, चीन की यांग्ट्सी नदी जिसे लोग 'रीवर आफ सौरो' कहा करते थे और जिससे लाखों मनुष्य हर साल परेशान रहते थे आज इन तीन-चार वर्षों में वह नदी सुख और समृद्धि की नदी बन गयी है। आज एक टूटे बांध की समस्या को लेकर हमारे इंजीनियर तीन-चार साल फाइलों के आवागमन में लगा देते हैं। इतने अरसे में चीन का वह आश्चर्यजनक वे रीभर प्रोजेक्ट बनकर और तैयार होकर इन निकम्मे इंजीनियरों को और गैरजवाबदेह शासकों को चुनौती दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अब हमें कोई अधिकार नहीं रह गया है कि हम उत्तर बिहार की जनता की जिन्दगी के साथ अधिक खिलवाड़ कर सकें। यदि आप सारे भारत की खाद्य-समस्या को हल करना चाहते हैं तो कोशी, गंडक और बागमती योजना को शीघ्रातिशीघ्र अपनाना होगा और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये हमें फौजी ढंग से कोशिश करने की बात सोचनी होगी। चीन की सफलता की कुंजी यही थी।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार के बाढ़ के भयंकर दृश्य ने

---

करीब डेढ़ महीने से जन-जन के मस्तिष्क को आक्रान्त कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य-मंत्री का वक्तव्य सदन के सम्मुख हुआ था। उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि रुपये के आंकड़े बहुत कम दिखाये गये हैं। समयाभाव होने के कारण मैं सिर्फ चम्पारण जिले के बारे में कहूंगी। अध्यक्ष महोदय, चम्पारण जिले की क्षति के बारे में जो विवरण है वह काफी कम है। जो सरकार की तरफ से सहायता दी जा रही है वह बहुत नगण्य है। मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान खेतों की तरफ ले जाना चाहती हूं। दो-तीन वर्षों में बाढ़ का दृश्य जो हमारे सामने उपस्थित हुआ है वह बहुत

दर्दनाक है। आज हमारा देश आजाद हो गया है और हम आजादी की सांस ले हे हैं। सरकार को चाहिये कि वह हमारे दुख-दर्द को सुख में परिणत कर देने के लिये एक ठोस योजना शीघ्र ही बनावे जिससे जनता का दुख-दर्द कम हो। सरकार ने गत वर्ष और इस वर्ष ऋण देना बन्द कर दिया है। सरकार को चाहिये कि वह कोई ऐसी ठोस योजना बनाये, सक्रिय कदम उठाये, जिससे बाढ़ के प्रकोप को समूल नष्ट किया जा सके। मुझे आशा थी कि मुख्य-मंत्री के वक्तव्य में ऐसी ठोस योजनाओं का दिग्-दर्शन होगा जिससे बाढ़ पीड़ित जनता को आश्वासन मिलेगा लेकिन हमें उसका अभाव उनके वक्तव्य में दिखाई देता है लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से जो सहायता दी गई है, इसके लिये मैं धन्यवाद देती हूं। गंडक नदी में बाढ़ आने के कारण केसरिया, मझरिया तथा केटाहा थाने में बाढ़ का तांडव नृत्य देखने में आया है। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। इधर-उधर एक-आध मकान दिखाई पड़ता है। ऐसी दशा में चारों ओर बीमारी फैल रही है। लोगों की दशा दयनीय हो गई है। मैं सरकार को सुझाव दे देना चाहती हूं कि सरकार योजना बनाकर इसमें काफी रुपया खर्च करे। ढेकाहा, भलाही, ढोल आदि गांवों की बरवादी को रोकने के लिये योजना सिंचाई विभाग तथा लोक-निर्माण विभाग की ओर से तैयार की गयी थी। इसके लिये २६ हजार रुपये की योजना बनी थी। अगर इस रुपये को इस क्षेत्र में खर्च करने में कार्यान्वित किया जाता तो बहुत फायदा होता। मैं कहती हूं कि पूरी योजना को यथा-शीघ्र लागू क । उसके लिये उस क्षेत्र के लोगों पर पांच साल तक लगान वसूल करना रोक दिया जाय, सर्टिफिकेट जारी करना बन्द कर दिया जाय। इस बाढ़ के कारण धनी, गरीब, सब की दशा एकसी हो गई है। गरीब लोगों को मुफ्त में सहायता देकर सुधार किया जा सकता है। जो मजदूर हैं उन लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। उनको सरकार धन दे जिससे आज उनकी जो फाके की स्थिति है उसमें राहत मिल सके। सरकार ने १२ रुपया प्रति मन की दर से गल्ले की दूकान खोली है। इसके लिये वह धन्यवाद का पात्र है। पर मैं सरकार से बिनती करूंगी कि ८ रुपया प्रति मन की दर से गल्ला बेचा जाय। इतना ही कह कर मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि मैंने जो कुछ सुझाव दिया है उसे सरकार कार्यान्वित करे।

श्रीमती पार्वती देवी—उत्तर बिहार के सिर्फ पूर्णिया जिले के बारे में कह रही हूं।

---

आप समाचार पत्र में इसकी दयनीय हालत के बारे में पढ़ते होंगे। पूर्णिया जिले की स्थिति यह है कि इस जिले में १८ थाने बाढ़ से पीड़ित हैं। आजमनगर, कराही, कढ़वा तथा आमोद की स्थिति मैं किन शब्दों में यहां पर करूं। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि सरकार ने जो सहायता के लिये रकम दी है वह संतोषजनक नहीं है। सहायता के लिये कांग्रेस के लोग नाव से सहायता की व्यवस्था कर रहे हैं।

४० वर्ष के बाद इतनी भयंकर बाढ़ आयी है और हमारी प्रार्थना सरकार से है कि इसका मुकाबिला करने के लिये वह आम जनता को काफी सहूलियत दे। हमारे आजम-नगर थाने में ८० हजार आदमी हैं। मैं २०० गांवों का भ्रमण करके आयी हूं। वहां एक भी ऐसा गांव नहीं है जो जलमग्न नहीं हो। यहां हरेक साल बाढ़ आती है। गत वर्ष वहां चार बच्चे डूब गये थे और इस साल तीन बच्चे डूब गये हैं। सरकार इस बाढ़ का मुकाबिला करने के लिये कुछ नहीं कर रही है। सरकार को चाहिये कि बेकार मजदूरों के लिये मजदूरी की व्यवस्था करे ताकि उनको रोटी और कपड़ा मिल सके। महिलाओं के लिये मुफ्त चर्खे का एवं रस्सी-कारबार के लिये सहायता दी जाय और धान कूटनी की व्यवस्था की जाय। तकावी ऋण तो केवल जमीन्दारों औ बड़े-बड़े लोगों को मिलता है। बेकार किसान क्या करें, वे तो रोटी की तबाही से तड़पते रहते हैं।

हमारे यहां जिला बोर्ड की केवल एक सड़क नाम के लिये है। मैं वहां से ३१ तारीख को आयी हूं और मैंने देखा है कि उस दिन वहां सड़क पर किश्ती चल रही थी। कदमा और करमदीघी बाढ़ क्षेत्र हैं लेकिन वहां नाव का कोई इतजाम नहीं ह, इसलिये लोगों को काफी दिक्कत उठानी पड़ती है। जो बाढ़ क्षेत्र हैं उसके लिये सरकार पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं करती है। बापू ने कल्पना की थी कि हम देहातों को सुधारेंगे लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। देहातों में ट्यूब-वेल का कोई इन्तजाम नहीं है। अप्रील के महीने में जब मैं अपने इलाके में भूमिदान के सिलसिले में गयी थी तो मैंने देखा था कि वहां की हरिजन महिलाएं पीने के लिये तीन-तीन मील से पानी लाती थीं। मैंने इसके लिये काफी लिखा-पढ़ी की लेकिन आजतक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कहा गया है कि बाढ़ क्षेत्रों के लिये १,००० ट्यूब-वेल की व्यवस्था की जायगी लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है। आजकल भी जब मैं अपने इलाके में जाती हूं तो यह देखती हूं कि वहां की जनता गढे और कूप का पानी पीती है। सरकार का ध्यान इस ओर जल्द जाना चाहिये जहां की जनता पीने के पानी के लिये तड़प रही है।

अध्यक्ष—शांति, शांति।

(मध्यान्ह भोजन का अवकाश।)

श्रीमती कृष्णा देवी—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सभा भवन में बाढ़ के संबंध

---

में सरकार की ओर से मुख्य-मंत्री के लिखित व्यान को उप-मंत्री सुना चुके है। इसके लिये मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूं। सदस्यगण भी बाढ़ पीड़ित जनता के अभूतपूर्व कष्टों की ओर जोरदार शब्दों में सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। इसलिये मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है फिर भी चन्द वाक्यों के द्वारा निकट भविष्य में आने वाले संकटों की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहती हूं।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को दो हिस्से में बांटना चाहिये। पहला जहां की भदई और अगहनी एकदम नष्ट हो गयी है और गांव अभी भी पानी से घिरा है। अगहनी एकदम होने की आशा नहीं है। फागुन के पहले कोई फसल होने की आशा नहीं ह। भीषण बेकारी छाई हुई है। दूसरा जहां बाढ़ के पानी से भदई और अगहनी नष्ट हुई है। फिर भी कुछ अगहनी होने की आशा है, धान की रोपाई अभी हो रही है या हो सकती है। पहले इलाका को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित करना चाहिये।

मैं दरभंगा जिला के एक विशेष इलाके को लेती हूं जिसमें सदर थाना का दक्षिणी हिस्सा, वारिस नगर का उत्तरी पूर्वी, बहेड़ा थाना का दक्षिणी, रोसड़ा थाना का उत्तरी, विरौल थाना के सर्किल नं० २,४ तथा सिंगिया थाना का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा पड़ता है। इस इलाके में करेह, बागमती, कमला, जीवछ और नोनेया नदियों से भयानक बाढ़ तारीख २५ जुलाई, १९५४ को ही आई थी। इस इलाके के सभी गांव पानी से घिरे हैं। भदई और अगहनी का कोई निशान तक बाकी नहीं है। अगहनी होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। ७५ प्रतिशत लोगों के घर गिर गये है। सभी सरकारी या गैर सरकारी बांध तथा जिला परिषद् की सड़कें टूट गयी हैं। जहां फागुन के पहले कोई फसल नहीं हो सकती है, भीषण बेकारी छाई हुई है। जिला पर्षद् के सड़कों पर नाव चल रही है। सड़क संख्या १० पर पिपरा पुल से हथौड़ी घाट तक २०० परिवार के लोग और सड़क संख्या ३९ तथा १० पर हथौड़ी कोठी के पास १०० परिवार के लोग गृहविहीन होकर माल मवेशियों के साथ खुले स्थान में ४० दिन से रह रहे हैं। एकाएक करेह नदी में २९ अगस्त, १९५४ को ३ फीट पानी फिर बढ़ गया है।

ऐसे क्षेत्र के मध्य में हथौड़ी कोठी पर बहेड़ा थाना के हिस्से को सहायता देने के लिए एक सहायता-केन्द्र खुला है। मगर बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे पीड़ित सभी गांवों में आजतक १.० दिन का भी गल्ला इस केन्द्र के द्वारा नहीं पहुंच सका है। सहा-यता अफसर शिवशंकर प्रसाद सिंह से पूछने पर मुझे पता चला है कि मांग के अनुसार न गल्ला मिलता है और न कर्मचारी ही मिले हैं। मैं लाचार हूं। मुझे जहां तक जान-कारी है जितने दूर के वे इंचार्ज हैं सभी बातों की रिपोर्ट भी सरकार के पास कर दिये हैं। इस इलाके में पूर्ति-मंत्री के साथ जिलाधीश भी अपने सहयोगियों के साथ जा चुके हैं। श्री देव नारायण यादव सदस्य बिहार विधान सभा भी निरीक्षण कर चुके फिर भी वहां की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अगर इस इलाके की यही स्थिति रही तो वहां भयानक भूखमरी शीघ्र शुरू हो जायगी। अतएव मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि शीघ्र आने वाले संकट का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जायं। मैं सरकार से साफ बता देना चाहती हूं कि सरकार अभी जिस किसी तरह की सहा-यता भी लोगों को करेगी सब पेट में जायेगा। सरकार जांच कर इस क्षेत्र को अकाल पीड़ित घोषित करे। बहेड़ा सर्किल नं० १८ मौजे हथौड़ी तथा सनखैरहा से आर्यावर्त में दो भूखमरी की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। बहेड़ा थाना की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। बहेड़ा थाना कांग्रेस कमिटी ने सरकार से जांच की मांग की है। मैं इस संबंध में कुछ विशेष नहीं कह सकती हूं। लेकिन वहां की रिलीफ की कुव्यवस्था को देखते हुए इतना तो कह ही देना चाहती हूं कि अगर सरकार शीघ्र सुव्यवस्था नहीं करेगी तो सैकड़ों भूखमरी होने की संभावना है। मैं जिलाधीश को भी इसकी सूचना दे चुकी हूं। मेरा ख्याल है कि वहां के एस० डी० ओ० साहब के असावधानी के कारण वहां की हालत बिगड़ती जा रही है। शीघ्र इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री रामचन्द्र प्रसाद शाही—अध्यक्ष महोदय, मैं बाढ़ की भीषणता के भविष्य में कुछ

---

कहना नहीं चाहता हूं। इस विषय पर मुख्य-मंत्री के वक्तव्य में तथा अन्य बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। अभी तक जिन लोगों को सहायता दी जा रही है या दी गयी गयी है उससे मध्यमवर्ग के लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है। मध्यम वर्ग के लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए सरकार को सस्ते गल्ले की दूकान खोलने की जरूरत है। कर्ज जो दिया जाता है वह बहुत कम दिया जाता है और उसका सूद भी कड़ा होता है। इसलिए सरकार को सूद हटा कर या उसको कम करके देना चाहिए ताकि लोगों को उसे फायदा हो सके। जो खैरात अन्न दिया जाता है उसको मध्यम वर्ग के लोग नहीं लेना चाहते हैं और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के ख्याल से कठिन शारीरिक परिश्रम भी नहीं करना चाहते हैं।

मैं खास कर राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान अपने थाने की ओर से ले जाना चाहता हूं कि वहां जो बूढ़ी गंडक है उसके किनारे के ५-७ बस्तियों में बहुत से घर गंडक में गिर गये हैं और उनके बसने के लिए कोई चारा नहीं है। अतः उन्हें बसने के लिए सरकार को जल्द से जल्द व्यवस्था करनी चाहिए। अभी तक जो लैन्ड एक्वीजी-शन कानून है उससे जमीन लेने में बहुत वक्त लग जाता है इसलिये कोई कानूनी तरीका निकाल कर जल्द से जल्द जमीन दखल कर उनको बसाने का बन्दोबस्त करना चाहिए। विलम्ब होने से उनको बहुत कष्ट होगा। अन्त में मैं सरकार का पुनः ध्यान दिलाता हूं कि सरकार मध्यम वर्ग के लोगों को तथा निम्नस्तर के किसानों को सुविधा के लिहाज से बिलासूदी रुपया कर्ज के रूप में देने की व्यवस्था करे और वसूली का जो समय है उसको भी लम्बा कर देना चाहिये।

श्री ब्रजबिहारी शर्मा—अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से जो बर्बादी हुई है उसके बारे में सभी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं उसको मैं दुहराना नहीं चाहता हूं और सरकार की तरफ से जो कार्रवाई पूरी तत्परता के साथ की गयी है उसके लिये मैं उसको बधाई देता हूं। सबसे बड़ी मुस्तैदी और तत्परता का पता इससे चलता है कि जब बाढ़ शुरू हुई तो हमारे मुख्य मंत्री ने अपने कमिश्नर और कलक्टरों को यह हिदायत दे दी कि जितना रुपया इस काम के लिए स्वीकृत किया गया है उससे अधिक रुपया वे खर्च कर सकते हैं। यह उनके उदार मनोवृत्ति का परिचायक था। वे बाढ़ पीड़ितों के प्रति कितना हमदर्द हैं। उसके बाद जो प ड स्टेटमेन्ट इ सभा में दिया है उससे भी पता चलता है कि वे बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या नहीं करना चाहते हैं। जिन-जिन जगहों में बाढ़ आयी है वहां-वहां रिलीफ केन्द्र खोले गये हैं, लेकिन स ृचित साधनों के अभाव से लोगों को अधिक लाभ नहीं पहुंचा है। मुझे इसी से संतोष है कि सरकार ने पूरी तत्परता और मुस्तैदी के साथ रिलीफ वर्क प्रारम्भ किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। चम्पारण जिले में जहां से मैं आ या हू चार भयंकर नदियां हैं—बांसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। मेरा थाना मधुबन जहां से मैं आता हूं बागमती के प्रकोप से अत्यन्त पीड़ित है। अभी तक जितने कमिश्नर हुए हैं उसमें सोहनी साहेब ही पहले कमिश्नर हैं जिन्होंने सिकरहना नदी पार कर मधुबन गये हैं। इसके लिए वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने वहां के लोगों की बर्बादी को देखा है। फिर उन लोगों का दुख दूर नहीं हो सका तो इसके लिए यही कहा जा सकता है कि वे देखकर भी नहीं देख पाये हैं। सरकार जो सहायता कर रही है वह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सरकार को स्थायी रिलीफ का कार्य करना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

इसके अतिरिक्त मैं सरकार का ध्यान अपने थाने के सुगिया परदेशिया नाले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उसको बांधने में बहुत कम खर्च है और उससे लाभ बहुत है। सरकार को चाहिए कि इसको शीघ्रातिशीघ्र बांध दे जिससे वहां की बर्बादी रुक सके।

सरकार जो कोई कार्य करना चाहती है वह बड़े पैमाने पर करती है। इसका कारण होता है कि वह काम जहां का तहां पड़ा रहता है। इसलिए सरकार को छोटे-छोटे काम हाथ में लेना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, चम्पारण का वह हिस्सा जो १८ हजार एकड़ है दह जाया करता है, शस्यश्यामल हो सकता है। परन्तु सरकार तो बड़ी-बड़ी स्कीम बनाती है, एकउंट के फेरे में पड़ी रहती है और छोटी-छोटी स्कीमों पर कुछ ध्यान देती ही नहीं जिससे हम-लोगों को लाभ होने वाला है। इसलिए सरकार से मैं अर्ज करूंगा कि अपनी औकात के अन्दर ही कोई स्कीम बनावे जो सफल हो सके। छोटी-छोटी नदियों को बांधे। बागमती और गंडक को बांधने में सरकार को ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अति शीघ्र इस काम में सरकार हाथ लगा दे क्योंकि यह लोगों के लिए बड़ी हितकारक होगा। उन इलाकों के लोग सरकार को मदद करने के लिए भी तैयार हैं। यदि कोई योजना सरकार बनाएगी तो वहां की जनता से भी बहुत सहयोग मिलेगा। इन दो नदियों को बांध देने से मुजफ्फरपुर का इलाका भी जो बर्बाद हो जाया करता है रुक जायगा चूंकि इन्हीं दो नदियों से मुजफ्फरपुर का इलाका बर्बाद होता है। मनुरवा ठीकहां इलाके में भी उन बांधों को फिर से बांधने की जरूरत हो गयी है जो टूट गये हैं। उसमें हम समझते हैं १० लाख रुपया से अधिक खर्च सरकार को नहीं होगा। यह काम बहुत ही तत्कालिक है। इस बांध के टूट जाने से लोग तबाह हैं, दाने-दाने

बिना तरस रहे हैं। इन बातों को जब मैं राजस्व मंत्री जी से कहा कि वहां के लोगों से जो मालगुजारी वसूल किया जा रहा है उसे बन्द करवा दीजिए क्योंकि वे लोग आज तीन सालों से दह रहे हैं। तो वे बोले कि मैं वहां के सर्किल अफसर के यहां भेज देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज ऐसा वक्त आ गया है कि कोई सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए आप के द्वारा अर्ज करता हूं कि तुरत उन इलाकों में जो मालगुजारी वसूल की जा रही है तथा सर्टिफिकेट जारी किये जा रहे हैं बन्द करवाने की आज्ञा दें। इतना ही नहीं मैं तो कहूंगा कि उन बाढ़ पीड़ितों को सूद भी छोड़ दें और अब जो रुपया कर्ज के रूप में दें वह बिना सूद ही के दें।

अब मैं आपका ध्यान उन इलाकों की ओर ले जाना चाहता हूं जो गांव कट रहे हैं। जो गांव कट रहे हैं उसमें रंगरेज, छपरा, समंगिया, भीमलपुर, लक्षमिनियां तथा मैन मेहसी शामिल हैं। इन गांवों को बचाना तो बहुत मुश्किल है चूंकि नदी के गर्व में चला जा रहा है परन्तु उन इलाके के लोगों को दूसरी-दूसरी जगह बसाने के लिए आपको प्रबन्ध करना होगा। सर्कल नं० ८, ७, ६, ५ अभी तक पानी में है और उस महीने के १६ तारीख से पानी में है। उसमें अब रब्बी तक का पज भी नहीं हो सकती है। इसलिए इन इलाकों के लोगो के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना बहुत जरुरी है। सरकार बीज के लिए गेहूं देती है परन्तु परसाल ऐसा देखा गया कि लोग बीज के लिए गेहूं लेने से इनकार कर दिए थे और कहते थे कि क्या विश्वास है कि गेहूं खेत में जमेगा या नहीं। इसलिए सरकार से मैं अर्ज करता हूं कि तकावी का लोन जो अभी २०-२५ रुपया देते हैं ज्यादा कर दें। उसी पैसे से लोग अनाज खरीद कर खायेंगे और बीज बचा हुआ गेहूं खेत में बोने के लिए हिफाजत से रखेंगे। मैं सरकार से यह नहीं कहता कि लोगों को खूब रुपया दें चूंकि सरकार का खजाना का भी कोई हद है। परन्तु मध्यम वर्ग के लोगों के लिए तो प्रबन्ध करना ही होगा। उन लोगों के लोन का रुपया का सूद छोड़ना ही होगा और अब जो रुपया आप देंगे वह बिना सूद के देना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार करे या नहीं करे, मैं तो कहूंगा ही कि बागमती और गंडक बांध जल्द से जल्द बन्धवाने की व्यवस्था करे। बागमती से जो सुगिया, परदेसिया तथा नयागांव उप-नालें निकलते हैं उसको ठीक कराया जाय। इसके अलावे नहर निकालने की व्यवस्था करें। पीने के पानी का भी बहुत अभाव है इसका भी प्रबन्ध कराया जाय। परन्तु जब तक नलकूप ठीक नहीं कराया जायगा तब तक पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं हो सकता है। इसलिए जो कुएं भस गये हैं उसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाय ताकि पीने के पानी की समस्या हल हो जाय। इसके अलावे मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि राशन बांटने का प्रबन्ध पंचायतों के हाथ सौंप दें और गल्ला इतना सस्ता दें कि पंचायत गरीबों को सस्ते दर पर गल्ला दे सके।

मजदूरों की समस्या भी बहुत जटिल हो गयी है। बेचारे गरीब मजदूर के पास न तो पैसे हैं और न काम करने के लिए काम ही मिलते हैं। वे लोग कई-कई दिन से भूखे रह रहे हैं। इसलिए उन लोगों के लिए कोई ऐसा इन्तजाम किया जाय जिसमें रोटी-रोजी की समस्या हल हो जाय।

अब मैं सरकार का ध्यान मवेशियों की दर्दनाक दशा की ओर ले जाना चाहता हूं। मवेशियों को खाने-पीने के लिए तो दूर रहा बैठने के लिए भी जगह नहीं है। बहुत ज्यादे संख्या में मवेशी मर रहे हैं। मवेशियों को पत्ते काट-काट कर खिलाये जा रहे हैं। इसलिए मवेशियों के लिए भी कोई प्रबन्ध करना ही होगा। इसके अलावे बच्चों की हालत भी दयनीय है। अनेकों प्रकार के रोग बच्चों को हो रहे हैं। केवल संतोष इतना

ही है कि अभी वह रोग एपिडेमिक रूप नहीं फौर्म किया है। इसलिए पहले ही सरकार को प्रवन्ध करना चाहिए जिसमें बच्चे को जो रोग हो रहा है वह रुक जाय। अन्त में मैं इतना ही कह कर बैठ जाता हूं कि वहां जो दवा-दारू, अन्न, रुपये भेजे जा रहे हैं वे काफी नहीं हैं। इसलिए सरकार को अच्छी तरह निगरानी करनी चाहिए और काफी मात्रा में भेजना चाहिए जो पर्याप्त हो सके।

*श्री जमुना प्रसाद त्रिपाठी—मैं कांटी थाना का प्रतिनिधि हूं और आपके द्वारा सरकार का ध्यान उस थाने की दयनीय दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जहां के सब गांवों में एक इंच जमीन भी नहीं सूखी बची है। बाढ़ का पानी वहां पहले जल्दी नहीं जाता था मगर एक साल हुआ वहां कई बांध-बांध दिए गए और उनके कारण समूचा थाना बह गया। जब बांध टूटने की शंका हुई तो वहां के इंजीनियर को खबर की गयी कि उस बांध को बचावें। लेकिन हमारे बार-बार कहने पर भी उन्होंने बांध की खबर नहीं ली और वह बांध आखिर टूट ही गया। हमारे बार-बार कहने पर उन्होंने कहा कि हमारा बांध वह नहीं है और उसकी रक्षा हम नहीं कर सकते हैं। बांध के टूट जाने से कांटी, सकरा और बांकेपुर इत्यादि का बहुत हिस्सा बह गया। इस साल की बाढ़ में आपने देखा होगा कि तरह-तरह के सांप और गोजर पानी के साथ आते थे और जो लोग छप्पर पर रहना चाहते थे उनको वे दिक करते थे जिससे लोग छप्परों पर भी नहीं रह सकते थे। हमारा कहना है कि सरकार उस बांध की मरम्मत करावे और राजस्व मंत्री महोदय से हमारी अपील है कि जब उन्होंने जमीन्दारी सरकार के लिए ले ली है तो जिन बांधों की मरम्मत जमीन्दार कराते थे उनकी वह मरम्मत करावे। बाकी जो कार्य किया जा रहा है वह सब ठीक ही है। इन्हीं शब्दों के साथ में उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री तनुकलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां सदस्यों ने सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा की है मगर सरकार के कथनी और करनी का जमा खर्च लिया जाय तो चीफ मिनिस्टर का वक्तव्य ऐसा लगेगा कि बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी आंखों देखा है कि बाढ़ का प्रकोप २७ जुलाई को हुआ। उस समय मैं सहरसा गया था। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और मुरलीगंज के इलाके में मैं घूम रहा था। सैकड़ों लाशों को भसते हुए हमने देखा है। हजारों पशुओं को भसते हुए लोगों ने वहां देखा है।

अध्यक्ष—शांति शांति। आपने गलत शब्द का व्यवहार किया है जिसको आप किसी भी सदस्य के संबंध में नहीं व्यवहार कर सकते हैं। आप उसको वापस लें।

श्री तनुकलाल यादव—मैंने मेम्बर के लिए नहीं व्यवहार किया। मैंने मुख्य मंत्री के वक्तव्य के संबंध में व्यवहार किया है। (हंसी।)

अध्यक्ष—उस शब्द को आप उठाते हैं या नहीं?

श्री तनुकलाल यादव—मैं उसको वापस लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं २७ जुलाई से १० अगस्त तक सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और मुरलीगंज में घूमता रहा और मैंने हजारों मवेशी और सैकड़ों आदमियों को भसते हुए नदियों में देखा। अध्यक्ष महोदय,

वहां के अफसरों का ध्यान जरा भी उस ओर नहीं गया। बहुत-सी बस्तियों का पता नहीं। बस्ती की बस्ती दह गई। अभी तक बहुत-सी बस्तियों में सरकार के अफसर नहीं पहुंच हैं। बहुत-सी बस्तियों का हिसाब-किताब नहीं है कि वहां के मवेशी या लोग कहां गए और आज यहां सरकार को बधाई दी जा रही है। यह निकम्मी सरकार है। बोलती है कुछ और करती है कुछ। सहरसा जिले के बारे में जो नक्शा छपा है वह बिल्कुल गलत है।

सारा सहरसा जिला जलमग्न है। एक चप्पा जमीन कहीं भी सूखी नहीं है। आलमनगर थाने के बारे में मैं खासकर कहना चाहता हूं कि इंच भर भी जमीन सूखी नहीं है। रिपोर्ट करने वाले को जरा भी अन्दाज नहीं है जो कहता है कि ३,००० बीघा जमीन बाढ़ से बर्बाद हुई है। रिपोर्टर को जरा सावधानी से रिपोर्ट देना चाहिए। गलत रिपोर्ट नहीं देना चाहिए। एक-एक मौजा तीन-तीन, चार-चार हजार बीघे के रकबे का होता है। क्या और बाकी तीन हजार बीघे में पानी है और चारों तरफ बांध-बांध दिया गया है? पच्छिम में चौथम थाना और पूरब में पूर्णिया के बार्डर तक समूचा जिला जलमग्न है। सरकारी कर्मचारी गलत-गलत रिपोर्ट देकर लोगों को मारना चाहते हैं। सरकार के रिपोर्टर लोगों को बचाने का काम नहीं करना चाहते हैं बल्कि मारने का काम। आज मैं अपने थाने से आ रहा हूं। नाव पर छः घंटे का सफर करना पड़ा। ढोलबज्जा से नौगछिया की दूरी ६-७ मील है। पानी का बहाव ऐसा था कि जान खतरे में ही समझना चाहिये। आज मैं मुरलीगंज, सुपौल इत्यादि का दौरा करके आया हूं। मुझको कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिली। समूचा जिला जलमग्न है। कहीं भी नाव नहीं है। लोग बीमार है, दवा बिना मर रहे हैं। यह सरकार निकम्मी है, इससे क्या आशा-भरोसा किया जाय। रिलीफ अफसर जो रिलीफ बांटने गए हैं उनका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं है। कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेन्ट और हमने मिलकर कहा कि चार जगह आलमनगर, चौसा, पुरैनी और फुलौत में आप बांटने का सेंटर रखिए मगर उन्होंने न उनकी बात रखी न मेरी। फुलौत और पैना में सेन्टर रखा, वहां एक-एक दरवाजे पर सेन्टर था। जहां न खाने की दूकान थी, न बैठने की जगह थी। जो ७-८ मील से लोग नाव पर आते हैं। कई दिनों से लोग वहां भूखों रहते हैं। न कोई बाजार है, और न कोई रहने की जगह है। अफसर अपने बंगले से रिलीफ बांटते हैं। मनमानी करते हैं। लोगों को बैठने तक की जगह नहीं। इंक्वायरी किया जाय। मैं राजस्व मंत्री को चैलेंज के साथ कहता हूं कि इंक्वायरी करावें कि जितने बौंड्स (सरकारी कर्ज) बनाये गए हैं बोगस हैं। पैना और फूलौत केन्द्र में ऐसा काम ज्यादा हुआ है। सरकारी कर्ज का दुरुपयोग किया गया है। अपना नाम, बाप का नाम एवं जाति इत्यादि को बदलने में सरकारी अफसर का हाथ ज्यादे हैं। अफसरों ने मिलकर ऐसा किया है। क्यों किया है मैं नहीं कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा देखा गया है कि जाति, पेशा और नाम बदल कर बौंड्स (सरकारी कर्ज) ली गई है और इस तरह से सरकारी रुपये को लोग हड़प लेते हैं जिससे फायदे के बदले हानि ही होती है। देखाने के लिये सरकार कहती है कि मैंने लोगों को इतना कर्ज दिया लेकिन सब बेकार मालूम होता है। सरकार को चाहिये की वह रिलीफ का बंटवारा ठीक से करावे।

अध्यक्ष—आप संक्षेप में ही कहें।

---

श्री तनकेलाल यादव—अच्छी बात है।

आलमनगर, बीहपुर और नौगछीया का सारा इलाका पानी से डूब गया है और सारे इलाके में कोशी नदी समुद्र के समान बह रही है। जान खतरे में डाल कर और छः घंटे नाव पर रह कर हम नौगछीया स्टेशन पहुंच सके हैं, और तब किसी तरह यहां आए हैं।

अध्यक्ष—आपने स्वयं देखा है और हम लोग इन सारी बातों को सुन चुके हैं।

श्री तनुकलाल यादव—आपने सुना जरूर है पर रिपोर्ट में ये सारी बातें नहीं दी गई है

अध्यक्ष—आप का समय खतम हो गया। आप अब बैठ जायं।

श्री तनुकलाल यादव—अच्छी बात है। मैं इतना ही कह कर बैठ जाता हूं।

श्री महावीर राउत—अध्यक्ष महोदय, मैं दरभंगा जिले से यहां पर आया हूं और अभी समस्तीपुर में जो बाढ़ आयी थी उसके बारे में सदन के सामने में कुछ कहना चाहता हूं। समस्तीपुर सबडिवीजन के मोहिउद्दीननगर के इलाके को छोड़ कर सारा सबडिवीजन जलमग्न है। इतने बड़े इलाके का जलमग्न होने का क्या कारण है? दरभंगा जिले में कलवाड़ा-पुनमा बांध बहुत ही मशहूर बांध है जो १८ मील लंबा है। इसके बाद चमरबघा बांध भी बहुत ही मशहूर बांध है। डकहा बांध भी बहुत मशहुर बांध है। दलसिंगसराय के नजदीक इस साल बाढ़ का बड़ा प्रकोप था। रोसड़ा इलाके का भी वही हाल है। इस इलाके के उत्तर में करेह नदी, दक्खिन में गंडक नदी, पश्चिम में बागमती और पूरब में कमला नदी है और इन नदियों में बाढ़ आने से इस इलाके की हालत बहुत ही सोचनीय है। परसाल भी यहां पर बाढ़ का प्रकोप था और इस साल की बाढ़ ने तो वहां के किसानों की कमर ही तोड़ दी है। वहां के किसान बाढ़ के चलते बहुत ही तकलीफ में हैं। अभी जो सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। हमारे विरोधी भाई कहते हैं कि सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। लेकिन में कहता हूं कि सरकार की ओर से बहुत मदद वहां के लोगों को मिली है। ऐसा कहने से मैं सरकार की वकालत नहीं करता हूं बल्कि एक यथार्थ बात कहता हूं जिसको मैंने अपनी आंखों देखा है। सरकार की ओर से काफी अन्न और पैसे वहां के लोगों के बीच बांटे गये हैं। लेकिन हमारे विरोधी भाई कहते हैं कि सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली है। इस मौके पर मुझे युधिष्ठिर के यज्ञ की बात याद आ गयी। उनके यज्ञ में उनके विरोधी दुर्योधन को सामान बाटने के लिये दिया गया था और उसके हाथ में चक्र रहने से सामान कभी घटता ही नहीं था। लेकिन हमारे विरोधी भाइयों के हाथ में तो चक्र नहीं हैं। हमारी सरकार उनके लोगों को अन्न बांटने के लिए देती है। बांटने के लिये उनको अन्न देने पर भी वे हमारी सरकार की शिकायत करते हैं।

श्री त्रिवेणी कुमार—आपके हाथ में चक्र है?

श्री महावीर राउत—आपको तो बांटने के लिये दिया जाता है लेकिन दुर्योधन के जैसा आपके हाथ में चक्र ही नहीं है।

अध्यक्ष—आप दूसरे सदस्य की बातों का जवाब न दें। अपनी बातों को कहिए।

श्री महावीर राउत—मैं अपने सिंचाई मंत्री से यह कहूंगा कि कलवाड़ा-पुनम बांध को फिर से बंधवाने की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं होने से वहां के लोगों की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी।

अध्यक्ष—क्या वह बांध इस साल की बाढ़ में टूट गया था?

श्री महावीर राउत—परसाल भी टूटा था, इस साल की भी बाढ़ में टूटा था और आगे भी टूटेगा।

श्री त्रिवेणी कुमार—अध्यक्ष महोदय, तब ऐसे बांध को बंधवाने से क्या फायदा जो हर साल टूट जाय।

श्री महावीर राउत—वह बांध परसाल टूट गया था और इस साल भी टूट गया है। सरकार को उसको बंधवाने के लिये जल्द से जल्द इंतजाम करना चाहिये। इसके लिये मैं खास करके अपने सिंचाई मंत्री से अनुरोध करता हूं। सरकार की ओर से नाव पर अन्न और सामान लेकर लोगों के बीच बांटा गया है। लोगों के लिये दवाई का भी इंतजाम किया गया है और यहां तक कि मवेशियों के लिए घास का भी इंतजाम किया गया। इतना होने पर भी हमारे विरोधी भाइयों की शिकायत यह है कि सरकार की तरफ से लोगों को मदद नहीं मिली है तब क्या कहा जाय!

एक चीज की तरफ मैं अपने राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि एन० सी० लोन की दरखास्त बहुत दिनों से समस्तीपुर सबडिवीजनल औफिस में पड़ी हुई है लेकिन कोई फैसला नहीं हो रहा है। उनकी दरखास्त पर जल्द हुक्म होना चाहिये और उनको पैसा मिलना चाहिये।

आखिर में मैं सरकार से कहूंगा कि वहां के बांधों के टूट जाने से वहां के लोगों की हालत बड़ी खराब हो गयी है इसलिए वहां के तीन मशहूर बांधों को और खास कर कलवाड़ा-पुनम बांध को जल्द बंधवाने के लिये हमारी सरकार इंतजाम करे। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी जो बाढ़ आयी थी और उसके चलते इस बिहार राज्य में इतना बड़ा सवाल पैदा हो गया है जिसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। अभी हाल ही में हमारे मुख्य मंत्री का यहां पर एक वक्तव्य हुआ था लेकिन उसमें भी क़ाफी वर्णन नहीं था। आप जानते हैं कि यहां पर पहले बाढ़ आयी और उसके डेढ़ महीने बाद फिर से बाढ़ आयी। जहां उत्तर बिहार में बाढ़ पर बाढ़ है वहां दक्खिन बिहार में सूखार है। अगर यह कहा जाय कि सारे बिहार में सूखार या बाढ़ है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। जिस समय हमारे मुख्य मंत्री का वक्तव्य तैयार किया गया था उस समय सूखार का अंदाजा नहीं लगाया गया लेकिन आज हमलोग उसको भी महसूस कर रहे हैं और जहां पर बाढ़ के चलते ७०

लाख आदमियों पर संकट की बात कही गयी है वहां पर मेरे ख्याल से इस सूबे की आबादी के ७० लाख आदमियों को छोड़ बकिये करीब ३ करोड़ लोग इस सूखार या बाढ़ से ग्रस्त हैं। ऐसी हालत में जहां पर ५० करोड़ बाढ़ की क्षति का अंदाजा लगाया गया है वहां पर मेरा ख्याल है कि ऐसी परिस्थिति की क्षति का अन्दाजा ५० करोड़ से के गुणा ज्यादा होगा। ऐसे संकटमय समय का मिसाल शायद इतिहास में भी खोजने पर कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा किसी देश में भी आज तक नहीं हुआ है कि बाढ़ पर बाढ़ और उसके बाद सूखार का नजारा हो।

आज आपके मारफत केन्द्रीय सरकार का और सारी दुनिया का ध्यान इस संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस संकट में मदद करने के लिए सबों को हाथ बटाना चाहिये। आप जानते हैं कि बिहार कृषि प्रधान देश है, यहां के ८६ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस संकट का रूप कितना भयंकर है। सिर्फ एक सिलवर लाइनिंग यानी आशा की रोशनी मुझे देखने को मिलती है। वह यह है कि यह संकट इतना भयानक है कि हमलोगों को इसके बारे में सोचने के लिए बाध्य करता है। और इसकी अहमियत को मद्दे नजर रखते हुए जब हम वक्तव्य को पढ़ते हैं तो मुझे इतना संतोष जरूर होता है कि इस संकट के स्थायी उपाय की ओर सरकार का ध्यान गया है। नदियों में बांध बांधने के लिए या सिंचाई के इंतजाम करने के लिये इस वक्तव्य में इशारा मिलता है। जहां तक उत्तर बिहार का सवाल है वहां के ऐग्रीकल्चरल एकॉनोमी की मदद पहुंचाने के लिए इण्डस्ट्रियल एकॉनमी कायम किए बिना परमानेंट सौल्यूशन नहीं मिल सकता है। मैं विकेन्द्रीयकरण के सिद्धांत को मानता हूं। जहां तक साउथ बिहार का सवाल है वहां इरिगेशन का काफी प्रबन्ध होना चाहिए। उत्तर बिहार में छोटे-छोटे उद्योग धन्धा कायम करने के लिये जितने कल पुर्जे की जरूरत हो वह दक्षिण बिहार में बन सकते हैं और इस तरह से एक हिस्सा दूसरे हिस्से का सम्पूरक बन सकता है। पंच-वर्षीय योजना या दस-वर्षीय योजना या जो काम शिक्षा, विभाग, कृषि विभाग या दूसरे विभाग का हो वह उसी योजना से जोड़ा जाना चाहिए। उसकी तरफ इशारा वक्तव्य में किया गया है। मगर वह काफी एक्सटेन्सिव नहीं है।

जब तक स्थायी सामाधान नहीं हो पाता है तब तक इन्टरीम रिलिफ का इंतजाम करना होगा। यद्यपि इस ओर स्टेटमेंट में इशारा किया गया है फिर भी उसमें कमी नजर आती है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है और मैं भी उसका इस्तेमाल करना चाहता हूं उसके लिए आप मुझे माफ करें। जब कोई देश युद्ध में शामिल हो जाता है और उससे उसको जितनी क्षति पहुंचती है, और जितनी बर्बादी होती है वह किसी हिसाब से इस बाढ़ या सूखार की क्षति से ज्यादा नहीं पाया जाता है। मगर फर्क इतना ही है कि लड़ाई का सामना करने के लिये राष्ट्र का सारा साधन इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्र में जितने कारबार है उसको लड़ाई के काम में लगाया जाता है। उस वक्त यह नहीं देखा जाता है कि कौन विरोधी मंच में है और कौन सरकारी मंच पर है। दोनों मिल कर लड़ाई का मुकाबला करते हैं। हम चाहते हैं कि ठीक उसी तरह लड़ाई के तौर पर इस संकट का भी मुकाबला करना चाहिए और सारे प्रान्त में सहयोग से काम करना चाहिये। अंग्रेजों को निकालने के लिये और स्वराज्य स्थापना करने के लिए जिस तरह से सभी पार्टी के लोग इकट्ठे हो कर काम किए थे ठीक उसी तरह इस हमले का भी सामना करना चाहिए। आज हालत क्या है ? एक तरफ करारोपण बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी इसी रफ्तार में बढ़ता जा रहा है। मिसाल के लिये आप देखें

कि छोटे-छोटे इरिगेशन के काम के लिए क्या किया जाता है। जिस ठीकेदार को काम दिया जाता है वह कुछ रुपया खर्च करता है और कुछ खा जाता है। ताकि रुपया खाने में उसको सुविधा हो इसलिए पदाधिकारीगण को भी घूस देता है। ऐसे छोटे-छोटे काम जिसके लिए औद्योगिक हुनर की जरूरत नहीं है स्थानीय लोगों से करा सकते थे और इस तरह से लोगों के दिल में एक राष्ट्रीय जागरण पैदा कर सकते थे। जब तक यह भावना पैदा नहीं होती है तब तक राष्ट्रीय संकट का सामना ठीक तरह से नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष—आपके कहने का क्या मतलब है! क्या आप यह चाहते हैं कि लघु सिंचाई के सम्बन्ध में जितना काम होता है सब लोगों से कराया जाय?

श्री जमुना प्रसाद सिंह—हुजुर मेरे कहने का यह मतलब है कि लोगों के दिल में ऐसी भावना पैदा करनी चाहिए कि जरूरत हो तो लोग टोकरी और कुदाल लेकर मिट्टी काटने में भी जरा सा न हिचकें। चीन का मिसाल हमलोगों के सामने है। छोटे-छोटे लघु-सिंचाई का काम जिसमें न औद्योगिक ज्ञान, न लोहा, न सिमेंट की जरूरत है, इस तरह के काम के लिए लोगों को टैक्स न करके उनके सहयोग से काम करना चाहिए। ऐसा करने से नौकरशाही में घूसखोरी भी बहुत हद तक घट जायेगी। जब घूसखोरी की बात कही जाती है तब मंत्री महोदय कहते हैं कि आप जेनरलाइज न करके खास मिसाल दें। मगर उससे सवाल हल नहीं होता। इसलिए उस बीमारी के तह पर जाना चाहिए। आप जानते हैं कि चीन ने ८० दिन में वह काम किया जो हमारे यहां ६ वर्ष में भी नहीं हो सकता है। इसकी बुनियाद क्या है। इसकी बुनियाद यह है कि उनमें जो राष्ट्रीय भावना है वह यहां नहीं है। तकलीफ को रफा करने के लिए तकलीफ में पड़कर भी यदि हमलोग सभी इकट्ठा होकर संकट निवारण का काम नहीं करें तो फिर कब कर सकते हैं! हमलोगों में से कुछ लोग माननीय डा० श्री कृष्ण सिंह या माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में काम कर चुके हैं और अभी भी करना चाहते हैं। इसलिए सभी दलों से सहयोग लेकर इस संकट का सामना करना चाहिए।

आज १० लाख का सवाल नहीं है बल्कि ३ करोड़ जनता का सवाल है जो पीड़ित हैं। जो सूखार में पड़े हुए हैं उनको भी साहाय्य देना है। ग्रैच्युटस रिलिफ के बारे में हमारे साउथ बिहार के दोस्तों ने जो प्रस्ताव किया है वह ठीक नहीं है। हम सभी लोग चाहते हैं कि सूखार क्षेत्र में भी रिलिफ दिया जाय। वह रिलिफ काम कराके या कर्ज देकर हो और बाढ़ से जो पीड़ित गांव हैं वहां मेडिकल रिलिफ, कर्ज और ग्रैच्युटस रिलिफ इत्यादि का काम होना चाहिए। भ्रष्टाचार का नीचे दर्जे में शिकायत है। स्थायी समाधान में तो कुछ दिन लगेंगे मगर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस काम को पूरा करने के लिये जो भी खर्च करना और कार्रवाई करनी है वह आपको करना चाहिए और जब तक स्थायी समाधान न हो जाए तब तक बचाव के काम पर विशेष ध्यान देना चाहिए इसलिए कि इसमें बहुत असफलता हुई है। सरकार ने माना है कि आपके पदाधिकारी तैयार नहीं थे.......................।

अध्यक्ष—अब समय का उल्लंघन हो रहा है।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—बहुत अच्छा हुजुर, अभी बोलना तो कुछ और था लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री वशिष्ट नारायण—अध्यक्ष महोदय, हाल की बाढ़ ने उत्तर विहार को सर्वनाश कर दिया है। उनमें दरभंगा जिला सब से अधिक बर्बाद है। दरभंगे जिले का क्षेत्रफल २१,३३,४१९ एकड़ है। जिनमें से लगभग १७ लाख एकड़ जमीन बाढ़ग्रस्त है। इस जिले के आबादी के योग्य लगभग १५ लाख एकड़ जमीन बाढ़ग्रस्त है। क्षति का अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अभी सारा जिला बाढ़ के लपेट में है फिर भी अनुमान से कहा जा सकता है कि १६ करोड़ रुपये की क्षति होगी। इस जिले में कुल धान की खेती लगभग १३,४५,६९० एकड़ में होती है। और मकई की खेती ३,९३,८२६ एकड़ में होती है। बाढ़ से धान और मकई की क्रमशः ८०-९० प्रतिशत फसल की बर्बादी हुई है। ५-७ हजार गांव बाढ़ ग्रस्त हैं। और लगभग २५ लाख आदमी बाढ़ के चपेट में हैं। इस जिले के ६० प्रतिशत गांव और ७५ प्रतिशत लोग बाढ़ के चंगुल में हैं। दरभंगा जिला में भी सबसे अधिक क्षतिग्रस्त समस्तीपुर सबडिवीजन के वारिसनगर, रोसड़ा, सिंगिया थाना हैं। वारिसनगर थाने में २३४ गांव हैं। वह १८ सर्किल में विभक्त है। उसकी आवादी २,४३,०२६ है। यह थाना १९६ वर्गमील में फैला हुआ है। सम्पूर्ण थाना बाढ़ के चपेट में है। और इस थाने की सम्पूर्ण आवादी बाढ़ के चंगुल में है। इस थाने के हर गांव टापू की तरह नजर आ रहा है। इस थाने में सहायता का कार्य योजनापूर्ण ढंग से नहीं हुआ है। इतना बड़ा थाना जो कि जल से भरा हुआ है वहां सिर्फ ३५ नावों का प्रबन्ध किया गया है। रिलीफ का काम ठीक से नहीं हो रहा है। गल्ला का वितरण बेढंगे और अनियमित रूप से होता है। दवा, डाक्टर, पथ्य, मवेशी के लिए चारा का कोई प्रबन्ध नहीं है, कहीं-कहीं पर सयाने आदमी को २।। सेर और बच्चों को १। सेर के हिसाब से गल्ला दिया जा रहा है। कहीं-कहीं पर तो इससे भी कम एक सेर, आध सेर और तीन छंटाक के हिसाव से दिया जा रहा है। वारिसनगर थाने के पूर्वी इलाके, जैसे हसनपुर, सादिकपुर ग्राम पंचायत राज्य वगैरह में तो सिर्फ एक बार गल्ला २८ अगस्त तक मिला है। वह भी एक सेर और आधा सेर के हिसाव से। मिल वाले कुंडा को जलावन के काम में लाते हैं और कोइला भी जलाने के लिए सरकार से लेते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें सरकार हिदायत करे कि वे ऐसे वक्त में मवेशियों के लिए कुंडा का प्रबन्ध करें। गल्ला का केन्द्र वहुत दूर-दूर पर हैं जिससे लोगों को आने-जाने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि नजदीक-नजदीक अन्न का केन्द्र होना चाहिये। कर्जे के वटवारा में देखा जाता है कि बटाईदारों को रुपया नहीं दिया जाता है। ऐसा आदेश सरकार की ओर से होना चाहिए कि बटाईदारों को भी रुपया मिले क्योंकि अधिकतर लोग बटाई पर ही अपनी जीविका चलाते हैं। अभी किसान लोगों को २० रु० प्रति बीघा के हिसाब से कर्ज दिया जाता हैं। मेरे ख्याल में उन्हें १०० रु० प्रति बीघा के हिसाव से मिलना चाहिये। हालां की जिनके पास रसीद नहीं है उन्हें रुपया नहीं दिया जाता है। सरकार को आदेश देना चाहिये कि उन्हें भी रुपया मिले। क्योंकि इस थाने के लोग तीन वर्षों से बराबर वाढ़ग्रस्त हैं। वारिसनगर थाने के अन्दर तीन-चार प्रमुख बांध हैं जिनके बारे में कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। एक चमरवड्डा वांध है। जहां काम शुरू हुआ तो मैं १०-११ जून को वहां गया और बांध का निरीक्षण किया और मैंने देखा कि बांध का निर्माण-कार्य ठीकेदार एवं अधिकारी मनमाने ढंग तथा लापरवाही से कर रहे हैं, एक-एक मन के रक्का

पर बांध तैयार किया जा रहा है। उस पर घूम सूर नहीं दिया जा रहा है तो मैंने सिंचाई मंत्री और उनके सम्बन्धित अधिकारियों के पास इस आशय का पत्र लिखा कि ठीकेदार एवं अधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहें हैं जिसका नतीजा यह होगा कि बरसात में पानी बरसने पर वह बांध धंसेगा और बाढ़ आने पर पानी ऊपर से बह जाएगा। वही हुआ कि उसी पत्र के जांच के सिलसिले में मुजफ्फरपुर से कोई इञ्जीनियर २४ जून को समस्तीपुर में आए थे। जब मैं उधर से गुजरा तो उनसे बातें हुई और उन्होंने कहा कि आपलोग हमारे काम में दखल देते हैं, आप इञ्जीनियर नहीं हैं। हमने कहा कि बांध जो तैयार हो रहा है वह गलत ढंग से। बरसात आने पर जरूर धंसेगा, टूटेगा। इस पर उन्होंने कहा कि यह हमारी जवाबदेही है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इञ्जीनियर साहब ने बातें की। आखिर में नतीजा यही हुआ कि वह बांध टूट गया। जिस तरफ मैंने अपने पत्र में इशारा किया था। ठीकेदार और अधिकारी की लापरवाही के कारण यह बांध बर्बाद हुआ, उस इलाके के लोगों का सर्वनाश हुआ। अतः सरकार से मेरी अपील है कि ठीकेदारों और उस मुजफ्फरपुर के इञ्जीनियर जिनका नाम शायद राम लाल साहब है, जो अपने को जवाबदेही मानते थे जो सही माने में अपराधी हैं भी सरकार मुनासिब सजा दें।

कटैला को चिलनहर योजना से मैं समझता हूं कि इस नहर योजना से किसी गांव या किसी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं बड़े ही दावे के साथ कहता हूं कि इस इलाके के किसी गांव को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। वरन् १०, ११, १२ और १५ सर्किल का सर्वनाश और सर्किल ६ का कुछ अंश क्षतिग्रस्त होता जा रहा है और यह इलाका कंगाल होता जा रहे है यदि उस इलाके के लोगों को वहां से नहीं हटाया गया तो वे बर्बाद हो जाएंगे। उस बर्बादी और सर्वनाश से अगर सरकार ने नहीं बचाया तो उस नहर को भर देने की बात लोग सोच रहे हैं। इसलिए सरकार उस इलाके के लोगों को बचाने का प्रबन्ध करें नहीं तो उस इलाके के लोग नहर को भर देने को तैयार हैं।

मधुआपुर-टारा बांध जो तीन लाख की स्कीम थी, तैयार किया गया। लेकिन बाढ़ आ जाने से वह बांध भी टूट गया। अभी भी देखा जाय तो मालूम होगा कि जगह-जगह सुराख हो गया है। इलाके के लोगों से दरयाफ्त करने पर मालूम हुआ कि बांध कमजोर बना था, बांध पर धूमसूर नहीं दिया गया था, बाढ़ आने से कुछ रोज पूर्व ही बांध तैयार हुआ था। लहेरियासराय से मुजफ्फरपुर जो सड़क जाती है वह कई जगहों में टूट गई है। मधुरापुर-टारा बांध के टूटने के कारण ही सड़क की ऐसी हालत हुई है।

घोघड़ाहा बांध नहीं होने के कारण इस थाने के सर्किल नं० ६, ५, ७, १३ की अकथनीय क्षति हुई है। अतः सरकार उस बांध को जल्द तैयार करावे।

उस सम्बन्ध में वहां के अधिकारी से बराबर लिखा-पढ़ी हो रही है लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो सकी।

हमारे माननीय सदस्य महावीर बाबू ने पुनमा और करवला बान्ध का जिक्र किया है, उन्होंने बतलाया है कि उस बान्ध से रोशड़ा थाने के इलाके के लोगों को फायदा होगा। वारिसनगर थाने के लोगों को इस बान्ध के चलते बहुत क्षति है। और रोसड़ा वाले को भी कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि तीन साल से पुनमा और करवला टूट जाता है। अतः उस बांध का निर्माण नहीं होना चाहिए, जब तक कि पानी का सर्वे न करा लिया जाए, और पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही सरकार को कोई कदम उठानी चाहिए।

*श्री सहदेव महतो—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री का जो वक्तव्य निकला है उसको मैंने ध्यानपूर्वक सुना है और कल से माननीय सदस्यों द्वारा इस बाढ़ के प्रकोप पर जो तवाही और वर्बादी हुई है उस पर काफी वादविवाद हो चुका है। अभी आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो माननीय मुख्य मंत्री की रिपोर्ट पेश की गयी वह भी अधूरी कही जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की तरफ से जो तबाही और बर्बादी को दूर करने के लिए मदद दी गयी है वह प्रशंसनीय है और इसमें भी शक नहीं है कि सरकारी अधिकारी भी जिस तत्परता के साथ एवं लग्न के साथ और जिस भावना से प्रेरित होकर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में, काम किया है वह भी प्रशंसनीय है। गड़बड़ियां कुछ जरूर हुई हैं जिसके बारे में हमारे विरोधी दल के भाई लोगों ने भी महसूस किया है। और जैसा श्री कर्पूरी ठाकुर ने भी कहा है कि ६० प्रतिशत आदमियों ने ईमानदारी के साथ काम किया है। जो कोई काम होता है उसमें गड़बड़ियां होती हैं और होती रहेंगी। मुझे भी नाव पर चढ़ कर देहात में घुमने का मौका मिला। ऊंचे तबके के अफसर जो आइ० ए० एस० हैं और मुजफ्फरपुर में रहते हैं हमारे साथ घूम रहे थे। मैंने देखा कि किस लग्न के साथ वे काम कर रहे थे। तीन दिनों तक उन्होंने स्नान तक नहीं किया और जव नाव पर चढ़े हुए थे तो वर्षा होती थी और चार बार वे भींग गये थे लेकिन कभी भी थके हुए नहीं मालूम होते थे। इतना ही नहीं दलसिंगसराय के अंचल अधिकारी घूमते-घूमते पानी में डूब गये थे लेकिन तैर कर निकले। इस तत्परता के साथ काम किया गया। यह तो सरकार की मदद की बात हुई और अफसरों ने किस तरह से काम किया है।

प्रीकौशनरी मेजर के बारे में मेरी शिकायत है। हमने देखा है कि जब बाढ़ आयी तो हमारे प्रमुख मंत्री ने कमिश्नर को और डिस्ट्रिक्ट अफसर को ब्लैक चेक भेजा कि बाढ़ ग्रस्त लोगों को मदद की जाय। लेकिन प्रीकौशनरी मेजर के बारे में हमारी शिकायत है। हम अपने क्षेत्र की बात कहते हैं कि अगर ५०० रुपया खर्च करके बान्ध बनवा दिया जाता तो हजारों बीघा जमीन की वर्बादी जो बाढ़ की वजह से हुई है बच जाती। अधिकारियों को कहा गया कि इतनी मदद दीजिए जिसमें लेवर को खाने भर पैसा मिल जाय। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नरहन वान्ध के बारे में अधिकारियों से कहा गया लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं हुआ। प्रीकौशनरी मेजर के सम्बन्ध में इसलिए मेरी शिकायत है। अगर पहले से प्रीकौशनरी मेजर लिया गया होता तो इतनी तबाही और वर्बादी नहीं होती। गत वर्ष भी तवाही और बर्बादी हो जाने के बाद कांफ्रेंस हुई। बहुत से लोग बोले लेकिन पहले से तैयारी नहीं की गयी। चमरबंधा बान्ध टूट गया मगर सरकार की तरफ से कोई तैनाती नहीं थी। वहां के ठीकेदार ने ५०० बोरा सिमेंट बेच दिया लेकिन कोई प्रीकौशनरी मेजर नहीं लिया गया। अगर प्रीकौशनरी मेजर लिया गया होता तो कोई क्षति नहीं होती। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार पहले ही से प्रीकौशनरी मेजर ले। वक्तव्य में एक खतरेनाक बात जो है वह मास्टर प्लान का है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि छोटे-छोटे वान्ध को बनवाने की कृपा करें। इमरजेंसी फ्लड सर्विस सरकार जल्द कायम करे। परसाल भी कमीशन बनाने की बात चली लेकिन कमीशन नहीं बनी। मेरा सुझाव है कि बाढ़ आने के पहले ही सब लोग तैयारी करें और सतर्क रहें।

रुपये के बारे में मेरा यह कहना है, जैसा श्री कर्पूरी ठाकुर ने कहा है कि मिट्टी के घर वालों को कम से कम १०० रुपये और दूसरों को ५० रुपये मिलने चाहिए। रुपया ठीक समय पर नहीं मिलता है क्योंकि केन्द्रीय सरकार से वातचीत करने में देर होती है और उस क्षेत्र में मदद पहुंचने में देर होती है। इतना ही कह कर मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपेन्द्र नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, उत्तर विहार में खासकर कोशी, कमला, गंडक इत्यादि नदियों से जो भीषण बाढ़ आई है उससे जो नुकशान हुआ है उसका आंकड़ा माननीय मुख्य मंत्री ने जो प्रस्तुत किया है अगर वह सही सही मान लिया जाय तौभी इतना काफी है। मैं सहरसा जिले के सम्बन्ध में आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सहरसा जिले में बहुत वर्षों से बाढ़ आती रही है। इस बार भी बाढ़ आई और कुछ नये स्थानों में भी आई। इससे बहुत बड़ी क्षति हुई। कोशी मुक्त जगहों में भी अचानक बाढ़ आ गयी। वहां तीस वर्षों के बाद बाढ़ आ जाने से वहां के लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हुई। वहां सरकारी सहायता चार दिनों के बाद पहुंचायी गयी। मैं जिस जगह में था अपने इलाके में वहां चार-पांच दिनों के बाद सरकारी अधिकारी पहुंचे और तब नाव की व्यवस्था की जा सकी। चार दिनों तक कोई खबर लेने वाला नहीं था। सरकारी काम अच्छी तरह से होता है लेकिन विलम्ब से होता है। मैं उसके लिये सरकार को दोषी नहीं मानता। मैं इसका दोष अफसरों पर देता हूं। सरकार ने जो सहायता दी है वह सर्वथा स्तुत्य है और उसकी मैं सराहना करता हूं। हमें संतोष है कि सरकार जो रिलीफ दे रही है वह संतोषप्रद है पर वह समय पर नहीं मिलती है, यह दुखप्रद है। मैं कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं, वह यह है कि आप उन गरीबों को रिलीफ देते हैं जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन ऐसे खेतिहर किसान जो लोग खैरात खाना पाप समझते हैं उनके लिये सरकार कोई इंतजाम नहीं करती है और न उनको कर्ज देने की कोई व्यवस्था ही करती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप उन बहादुरों को जो खैरात खाना पाप समझते हैं सरकार लोन देने की उनके लिए व्यवस्था करे। हो सकता है सरकार को इसके लिये जोखिम उठानी पड़े। लेकिन सरकार को यह करना चाहिए। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में भीषण परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। अक्तूबर से स्थिति और भी खराब होगी उसके लिये मैं सरकार से कह देना चाहता हूं कि वहां रिलीफ वर्क शीघ्र शुरू कर दे। जिला परिषद् के सड़कों में ही नहीं बल्कि गांव-गांव के डगर (रास्ता) में काम किया जाय। मेरा सुझाव है कि रिलीफ वर्क जिले के सभी भागों में किया जाय। दूसरी बात यह है कि जिन गांवों में जहां चौरों में या गहरे जमीन में पानी लग गया है वहां पानी निकाल देने से रब्बी की फसल बोई जा सकती है और मकई की खेती समय पर की जा सकती है। इस प्रकार लोगों को कोने-कोने में रिलीफ द्वारा राहत मिल सकेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि रिलीफ थ्रू वर्क द्वारा चौरों का पानी निकाल देना चाहिये। इसके बाद में एक और बात कह देना चाहता हूं। पानी घटने के बाद बीमारी फैलेगी, जैसे मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, हैजा आदि। इसके लिए दवा की व्यवस्था होनी चाहिये। पीने के पानी का प्रबन्ध होना चाहिये। जिन-जिन गांव के कुएं बाढ़ के कारण बर्बाद हो गये हैं वहां काफी संख्या में ट्यूब-वेल देना चाहिये और कुंआ मरम्मती के लिये रिलीफ देना चाहिए जिससे गरीबों का दुख मिट सके।

उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया।

श्री उपेन्द्र नारायण सिंह—आप समय देने की कृपा करें। मैं अनुरोध करता हूं कि बाढ़ के कारण जिन लोगों की फसल बर्बाद हो गई है उनका लगान माफ कर देना चाहिये। और तमादी नालिस की तिथि बढ़ा देनी चाहिए जैसा कि श्रीमती राम दुलारी सिंह ने भी कहा है कि सरकार का जो तमादी का समय है ६ महीने के लिए उसको बढ़ा दिया जाय। किसानों की जमीन वर्बाद हो गयी है, उनकी फसल बाढ़ से नष्ट हो गयी है अगर अभी तमादी नालिश होगी तो गरीब किसान (लगान) मालगुजारी नहीं दे सकेंगे। उनकी जमीन निलाम हो जायेगी इसलिए तमादी नालिश बढ़ाकर गरीब किसानों को बचाया जाय। एक विषय के बारे में मैं और कह देना चाहता हूं वह यह है कि सहरसा जिले की फसल मारी गई है। इसलिए मैं एग्रीकल्चर टैक्स की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। जब फसल मारी जाती है तो एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगना चाहिये। फिर भी किसानों पर एग्रीकल्चर टैक्स का बोझ लादा जाता है। एग्रीकल्चर टैक्स की नीति में सुधार नहीं की जाती है जो उचित नहीं है। मैं कृषि मंत्री जी से विनतीपूर्वक आग्रह करता हूं कि इस पर गौर करें।

श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह—इस बार तिरहुत में भयंकर बाढ़ आई। हम लोग सदन में बैठ कर उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बाढ़ का पानी हम लोगों को भी जलमग्न कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, तूफानी ढंग से बाढ़ आई जिसकी मानव कल्पना भी नहीं कर सकता है। किसान चौरों में गये थे, वे बाढ़ के भीषण प्रकोप के कारण गंगा में बह गये। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह एक सौ वर्ष पहले तक इस जमीन पर इतनी बड़ी बाढ़ नहीं आई थी। इस पर भी इतना प्रलयंकारी दृश्य था। चारों और भयानक जहरीले सांप भरे पड़े थे। इस से कितने लोगों की मृत्यु हो गई। मजदूरों के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लोग भी पिसे गये। इस अवस्था में बिहार राज्य के संचालन करने वाले महापुरुषों की सराहना करता हूं जिन्होंने अपनी चेतना और सेवा से जनता की तकलीफों को दूर करने की कोशिश की। हमारे मुख्य मंत्री ने हर जगह जाकर दौरा किया है। तिरहूत में हमारे माल मंत्री और उद्योग मंत्री ने दौरा किया। उनकी जो इच्छा है, उनकी जो ईमानदारी है, उनका जो प्रयास है उसमें किसी को शक नहीं हो सकता है।

फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी गलतियों की वजह से लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है। मैं मंत्री मंडल के लोगों से अनुरोध करूंगा कि आपके मन में सेवा का जो भाव है उसके चालू होने में कहीं-कहीं दिक्कतें होती हैं और आप उनको देखने की कोशिश कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो सैकड़ों मानव प्राणी की जान बचा सकेंगे। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। हमारे यहां संकरा बांध है। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से जब परामर्श लिया गया तो उन्होंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री नारायण ठाकुर ने श्री मुकुटधारी सिंह, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा कि यदि वे इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहते हैं तो जनता इसकी मरम्मत करेगी। इस पर उन्होंने कहा कि यदि जन प्रयोग होगा तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। यदि प्रान्त के अधिकारी ऐसा करेंगे तो मानव की रक्षा कैसे हो सकती है। बाढ़ का पहला धक्का आया और सैकड़ों वस्ती, मानव और उनके मवेशी बह गये, इसलिये कि एक अधिकारी ने चेतावनी नहीं दी। मैं कहता हूं कि ऐसी घटना की आप जांच कीजिए और यदि मेरी बात गलत हो तो

मुझे भी चुनौती दीजिए। सरकार ऐसी परिस्थिति की जानकारी करे कि एक गलतफहमी के कारण सैकड़ों वस्ती पानी में वह गये। मुख्य मंत्री मुजफ्फरपुर गये थे उस समय श्री नारायण ठाकुर, जो ४० वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने मुख्य मंत्री से यह शिकायत की। ऐसी शिकायत उन्होंने ३० वर्षों में नहीं की थी।

दूसरी बात यह है कि मुजफ्फरपुर जिले में चन्द दिनों के लिए खैरात देना वन्द हो गया, जब इसकी खबर कमिश्नर को मिली तो उनको परेशानी हुई और उनको आश्चर्य हुआ। मैंने मुजफ्फरपुर से माल मंत्री को टेलीफोन किया और उन्होंने तीन घंटे के भीतर खबर दी कि इसकी इजाजत दे दी गई है। उसी दिक्कत के वक्त माल मंत्री मुजफ्फरपुर पहुंचे। तो एक तरफ भारत सरकार के लोग आ रहे हैं लेकिन गरीबों को राहत देने के लिये कुछ अधिकारी उचित करवाई नहीं करते हैं। आप इसकी जांच कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। जब आपके पास इतनी सद्भावना है और आपने यज्ञ ठाना है कि मानव को मरने नहीं देंगे तो आप यह देखें कि ऐसी दुःखद घटना क्यों होती है। हम आपसे यह अर्ज करेंगे कि वाढ़ तो हर साल आती है। आपने पिछले वर्षों में सेवा की है। इस वर्ष भी आपने सेवा की है और आगे भी समय आने पर करेंगे लेकिन इसका कोई स्थायी इलाज कीजिए, ताकि लोगों को इस दुर्भिक्ष से त्राण मिल सके। ऐसा करने से आपको भी संतोष होगा और सैकड़ों मानव को भी संतोष होगा। हमसे आपकी चिन्ता और जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, इसलिये आप इसका इंतजाम करें। मुजफ्फरपुर जिले में कर्ज जब बंटवारा होता है तो अधिकारी कहते हैं कि जहां हम कर्ज बांटते हैं वहां ग्रेच्युटस रिलीफ नहीं देंगे परन्तु दोनों दो चीजें हैं। ऐसा आप क्यों कहते हैं, आप इसकी जानकारी कीजिए और इलाज कीजिये।

अधिकारी वर्ग के लोग भी काफी जिम्मेदार होते हैं। लेकिन कहीं-कहीं अनुभवी अधिकारी के न होने से हानि भी होती है। सीतामढ़ी सबडिवीजन में नया सबडिवीजनल अफसर होने के कारण वहां के सहायता कार्य में बड़ी दिक्कत हुई है। लेकिन मुजफ्फर-पुर सदर सबडिवीजन में योग्य सबडिवीजनल अफसर रहने के कारण कठिनाई रहने पर भी समस्या का समाधान अच्छी तरह हुआ। इसलिये मैं आप से अनुरोध करता हूं कि ऐसे संकट की घड़ी में काफी योग्य पुरुष को रखें जो इस संकटयुद्ध में अच्छी तरह लड़ सकता है।

मैं तो श्री एस० वी० सोहनी की प्रशंसा करूंगा कि इस डिवीजन का कार्य भार यद्यपि उन्होंने तुरत ही संभाला है परन्तु उन्होंने परिस्थिति की गंभीरता को अच्छी तरह से समझा। जन सम्पर्क की स्थापना की तथा बाढ़ की समस्याओं को व्यावहारिक दृष्टि-कोण तथा पूरी तत्परता से समाधान करने का सफल प्रयास किया है।

इस वर्ष घर गिरनेवाली लोगों की संख्या ८० प्रतिशत है। पिछले वर्ष अपने २५, १५, १० रुपये दिये थे। लेकिन इस साल आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक रुपया दे सकें।

मैं एक बात और वताना चाहता हूं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिये अपने वच्चों के मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं लेकिन आपके पास आना पसन्द नहीं करते हैं। ऐसे वर्ग को आप सहयोग दीजिए। आप लोगों को विना सूद के रुपया दीजिए। आपको इसमें टेक्निकल डिफिकल्टिज होगी लेकिन आप सोचिए कि आप कैसे उसको सौल्भ कर सकते हैं। वेकार मजदूरों के लिये आपको मिट्टी के काम का एक साल के लिए प्रबन्ध करना चाहिये।

जो विद्यार्थी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कम दाम में उनके होस्टलों में राशन भेजने का प्रबन्ध होना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी ही भावी राष्ट्र के निर्माता हैं। उनको जर्जर होने से बचाने का प्रबन्ध करना जरूरी है। मुजफ्फरपुर में विद्यार्थियों की एक समिती बनी है, सरकार को चाहिए कि हर तरह से उस समिति को मदद दे।

सड़कें भी टूट गयी हैं और उनकी मरम्मत जल्द होनी चाहिये ताकि आवागमन की जो दिक्कतें हैं वे दूर हो जायं। इसकी दिक्कत के कारण हम लोगों तक रिलीफ भी नहीं पहुंचा सकते हैं।

अतः मैं अपनी ओर से आपके समक्ष कुछ ठोस सुझाव रखना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि इस पर अमल करने से बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का समुचित भला कर सकते हैं। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि सहायता कार्य और कुछ दिनों तक चलता रहे। कर्ज देने का कार्य शीघ्रतापूर्वक तथा देर तक चले क्योंकि मुजफ्फरपुर जिले में यह काम देर से शुरु हुआ। घर बनाने के लिये दी जाने वाली रकम कम से कम १०० रुपया हो। प्राकृतिक बिपत्ति संबन्धी कर्ज की रकम बढ़ाई जाय और उसके कायदा-कानून की पाबन्दी कम की जाय। रिलीफ केन्द्रों में दो अफसर बहाल किये जायं, जिनमें एक अन्न आदि का वितरण करावें और दूसरे कर्ज के बंटवारे के साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखें कि दुर्गापूजा की छुट्टी में सहायता कार्य में बाधा नहीं आने पावे। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि बाढ़ के फलस्वरूप दूसरी बिपत्ति अर्थात् संक्रामक रोगों से बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को मुक्त रखना चाहते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में नलकूपों का प्रबंध होना चाहिए।

परन्तु हमारी सारी उत्कंठा, सारे इन्तजाम पर पानी फिर जायगा, यदि नावों का प्रबंध पहले से करके नहीं रखा जायगा। इस संबन्ध में श्री सोहनी, कमिश्नर, तिरहुत डिवीजन के कार्यक्रम को सरकार ठोस रूप दे। साथ ही साथ गल्ले के गुदाम सदर मुकामों में न खोलकर गावों में खोले जायं, जहां से दुकानदारों को माल ले जाने में सुविधा हो। अस्थाई अस्पतालों की संख्या भी तत्काल बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में बढ़ाई जानी चाहिये। अनावृष्टि के कारण या अतिबृष्टि के कारण चाहे उत्तर में तबाही हो या दक्षिण में, आप इसकी ओर जल्द ध्यान दें।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। आप संक्षेप में बोलें।

---

श्री नीतिश्वर प्रसाद सिंह—यदि आपको मानव की रक्षा करनी है तो चाहे उत्तर के हों या दक्षिण के हों, सभी पांच तत्वों से समान रूप से बने हैं और आपका ध्यान सभी ओर समान रूप से जाना चाहिये। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी आत्मा को तकलीफ होगी। जय हिन्द।

श्री जीवत्स शर्मा हिमांशु—उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं उत्तर बिहार की बाढ़ की स्थिति के संबन्ध में कुछ सोचना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे दिनकर जी की वह कविता याद आ जाती है जिसमें उन्होंने हिमालय की प्रशंसा में अपनी कलम तोड़ दी है। मैं आपके द्वारा महाकवि दिनकर से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह पुनः एक ऐसी कविता लिखें जिसमें हिमालय द्रवीभूत हो जाय और फिर से हमारी ऐसी दुर्गति

न हो। सिर्फ इतना ही नहीं मैं अपने मंत्रियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप हिमालय के पास जाकर अराधना करें—और हिमालय को अपनी स्थानीय अवस्था से परिचित करायें तभी हमारे रमणीय उत्तर भारत का सौंदर्य रह सकेगा। अन्यथा मेरे सामने कोई दूसरी उपाय नजर नहीं आती।

मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां १६ तारीख से महानन्दा का प्रकोप शुरु हुआ। हमलोग नावों पर उस क्षेत्र में घूमते रहे। वहां मैंने देखा कि लोगों के घर कट-कट कर गिर रहे हैं। चारो तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है। मवेशियों को रहने के लिए कोई जगह नहीं है। एक तरफ महानन्दा का प्रकोप था और दूसरी तरफ वर्षा हो रही थी। लगातार इस तरह वर्षा होती रही कि लोगों ने महीनों तक सूर्य को नहीं देखा। लोग कहते हैं कि ३० वर्ष पहिले कभी इस तरह की बाढ़ नहीं आयी थी। लाखों एकड़ जमीन जिनमें फसलें लगी हुई थीं, बर्बाद हो गयीं। रिलीफ अफसर ने रिलीफ बांटने में जो तत्परता दिखलायी है उसे मैं नहीं भूल सकता। हमारे क्षेत्र में १२ सौ मन चावल बांटा गया है जो दाल में नमक के बराबर है। उत्तर बिहार की नदियों को बांधने के लिए सरकार २५ करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है लेकिन पूर्णिया की नदियों का कहीं नाम तक नहीं है। मैं सिंचाई मंत्री से अनुरोध करूंगा कि पूर्णिया की महानन्दा नदी का नाम भी जोड़ दिया जाय। हमारे यहां मवेशियों के लिए चारे की बहुत कमी है। इसके संबन्ध में बहिन रामदुलारी ने एक सुझाव दिया है कि मिलों से भूसी लेकर इन क्षेत्रों में भेजी जाय। इसका मैं भी समर्थन करता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं राजस्व मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कम से कम उन्हें डेढ़ साल का खजाना माफ कर देना चाहिये। इस साल का खजाना तो माफ कर ही दें अगले साल का भी आधा खजाना माफ कर देना चाहिये। बाढ़ से कुएं नष्ट हो गये हैं इसलिए ट्यूब-वेल का इन्तजाम होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में ,सबसे बड़ी क्षति पहुंची है। उसके लिए १ हजार ट्यूब-वेल देने की जरूरत है।

मैं अपने राजस्व मंत्री का ध्यान पूर्णिया जिला के जिलाधीश श्रीमान मोहन चौधरी जी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमलोग लगातार बाढ़ क्षेत्र में महीनों काम करते रहे हैं। जब हमलोग उनसे कुछ कहते थे तो उनको आश्चर्य मालूम होता था। वह झट व्यंग भरे शब्दों में कह दिया करते थे कि देवी जी को जरा शान्त रखिये इतना ही नहीं हमलोगों से मिलने में भी उनका समय नष्ट हो जाया करता था। क्या यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का व्यवहार हो सकता है। राजस्व मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये और उन पर उचित कार्यवाही करनी चाहिए। हमारे तुनुक लाल यादव जी ने जो आक्षेप किया है वह सही नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी के कुछ लोगों ने मदद की है लेकिन सभी ने नहीं किया है और वे काम करने से भागते रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्त्ता दिन रात जुटे रहे हैं। खाद्य मंत्री श्री किदबई साहब ने कहा है कि १२ हजार मन गेहूं और चावल देंगे। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि १२ रुपये मन गेहूं नहीं देकर ६ रुपये मन गेहूं का भाव कर दें तो लोगों को कुछ सहायता मिल सकती है। अन्यथा आज जनता के पास पैसे की इतनी कमी है कि वह अनाज नहीं खरीद सकेगी। बीज ठीक समय पर यदि नहीं पहुंचा तो हाहाकार मच जायगा। क्योंकि भदई तो गई ही रब्बी भी चली जायगी।

*श्री चुनका हेम्ब्रोम—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल से बाढ़ के संबन्ध में बहुत सदस्यों के भाषण सुने और हमारे मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उसको भी देखा। उन्होंने उत्तर बिहार की जो क्षति हुई है उसका विवेचन किया है और उसका नक्शा भी हमलोगों के सामने रखा है। उत्तर बिहार के लोगों को इस बाढ़ से जो कष्ट पहुंचा है उससे हमलोगों को काफी दुख है। उनका दुख हमारा दुख है। इस बाढ़ से उत्तर बिहार को ही नहीं धक्का पहुंचा है बल्कि सारे बिहार प्रांत बासियों को भी उससे महान कष्ट पहुंचा है। उत्तर बिहार में करीब डेढ़ करोड़ आदमी बसते हैं। वहां १ करोड़ २५ लाख एकड़ जमीन आबाद हुई थी। उसमें काफी क्षति पहुंची है। उससे जिन लोगों का गुजर बसर हो रहा था उनको काफी नुकशान पहुंचा है। उत्तर बिहार के लोगों के खर्च के अतिरिक्त जो अनाज बच जाता था उससे दक्षिण बिहार के लोगों को फायदा पहुंचता था। इस साल दक्षिण बिहार में भी अनावृष्टि की बजह से भदई फसल मारी गयी और धान लगभग ७० प्रतिशत नहीं रोपा गया। वहां अनावृष्टि के कारण अकाल की स्थिति पहुंच गयी है। इसलिए इस बर्ष वहां धान नहीं हो सकेगा। वहां भी करीब-करीब ढाई करोड़ आदमी बसते हैं। उनका गुजर बसर करना कठिन हो गया है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज तीन चार महीने से सरकार उत्तर बिहार में रिलीफ बांट रही है। लेकिन उसको बाढ़ की वर्बरता को दूर करने के लिये आज तक कोई काम नहीं कर सकी है। बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि कोशी बांधी जा रही है लेकिन आजतक कोशी नहीं बांधी गयी। आज हमलोगों को रिलीफ देने में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। अन्दाज लगाया गया है कि कोसी को बांधने में ३५ करोड़ रुपया खर्च होगा। इस साल सरकार ने यह भी अन्दाज लगाया है कि उत्तर बिहार की बाढ़ से ५० करोड़ के लगभग क्षति पहुंची है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां बाढ़ से इतने रुपये हर साल बर्बाद होते हैं वहां इन छोटी-छोटी नदियों को बांध दे और कोशी गंडक से जो क्षति पहुंची है उसको भी बांधने की कोशिश करे।

अध्यक्ष महोदय, दक्षिण बिहार के रहने वाले हमलोगों को भी काफी दुख है। छोटानागपुर, संथार परगना, भागलपुर के कुछ हिस्से, मुंगेर के कुछ हिस्से तथा पलामू वगैरह में अनावृष्टि के कारण हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए हम सरकार से अर्ज करते हैं कि उत्तर बिहार की तरह दक्षिण बिहार की तरफ भी जरा ध्यान दें। मैं यह नहीं कहता हूं कि उत्तरी बिहार के लोगों को मदद नहीं की जाय। उन्हें जैसी मदद की जा रही है उससे ज्यादा की जाय यदि वे सचमुच में तकलीफ में हैं परन्तु दक्षिणी बिहार की ओर भी सरकार अवश्य ध्यान दे। मैं उत्तर बिहार के प्रतिनिधियों से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह वे उत्तर बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए सदन में कह रहे हैं उसी तरह दक्षिण बिहार के लोगों के लिए सदन में कहें कि अनावृष्टि के कारण दक्षिण बिहार के लोग बहुत कष्ट में हैं और हमलोग भी उत्तर बिहार के पीड़ित लोगों की सहायता के लिए सरकार से अर्ज करेंगे और करते हैं।

इसके अलावे सरकार को मैं एक सुझाव देता हूं कि वह रिलीफ बांटने के लिए गैर-सरकारी लोगों को भी रखें। वे लोग भी रिलीफ बांटने के काम में मदद करेंगे। मैं एक बार फिर सरकार से अर्ज करते हुए बैठ जाता हूं कि जिस तरह उत्तर बिहार को मदद कर रहे हैं उसी तरह दक्षिण बिहार को भी अवश्य देखें नहीं तो दक्षिणी बिहार की जनता खतम हो जायगी।

श्री रामनारायण चौधरी—उपाध्यक्ष महोदय, जहां एक ओर यह बात सही है कि घटनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कहना चाहिए और दूसरी ओर यह भी सही है कि घटनाओं को मिनिमाइज नहीं किया जाय। हम आगे चलकर कहेंगे कि किस तरह बुरोक्रेटिक मेंटलिटी से सरकारी नौकरों ने उस रिपोर्ट को तैयार किया है जो मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिन सभा के सामने रखा था। बहुत सी बातों का वर्णन उस रिपोर्ट में की गई है। लेकिन कोई ऐसा ठोस कदम उठाने का जिक्र उस रिपोर्ट में नहीं है जिससे भविष्य में लोगों को बाढ़ के प्रकोप का सामना नहीं करना पड़े। जहां एक ओर हम सुनते हैं कि राजस्थान की मरुभूमि को हराभरा बनाने का इंतजाम किया जा रहा है, दूसरी तरफ हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तरी बिहार जो सारे भारत का उपवन और अन्न का भंडार समझा जाता था वह किस तरह आज बर्बाद हो रहा है। हर साल हम देखते हैं कि बाढ़ की स्थिति खराब होती जा रही है और हर साल यही कहा जाता है कि इस साल के बाढ़ ने पुराने सभी रेकर्ड को तोड़ दिया। सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलता है कि आखिर इस दुख का कब तक अन्त होगा। हम जानते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री तथा अर्थ मंत्री ने भारत सरकार पर काफी दबाव डालकर कोसी योजना के लिए भारत सरकार को राजी किया। आज भी जिस जोर-शोर से गंडक को बांधने की बात चल रही है उसी प्रकार बूढ़ी गंडक, बालन, जीबच, कमला, बागमती आदि नदियों के लिए सरकार को सोचना चाहिए था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार इन स्कीमों के बारे में कुछ भी सोचती विचारती नहीं है।

रिलीफ के संबन्ध में मुझे यह कहना है कि पर्याप्त रूप से मदद नहीं दी जा रही है। यह मैं मानता हूं कि कुछ अफसरों का काम सही तरीकों पर हो रहा है जिससे एक कल्याण राज्य की एक छोटी झलक देखने को मिलती है। सरकार के काम करने की कुछ ऐसी प्रणाली है जो समय पर काम नहीं कर सकती है। हमारे सिंचाई मंत्री इस राज्य में एक्सपर्ट्स का ह्वाइट एलिफैन्टस पाल रहे हैं। १९४६ के बाद से आज तक कोई ऐसी ठोस योजना या कोई ऐसी साइन्टिफिक सर्वे नहीं हुई या न कोई ऐसी योजना बनी जिससे लोगों को शीघ्रातिशीघ्र राहत मिले। मैं समझता हूं कि इन ह्वाइट एलिफैन्टस की महावत का अंकुश ऐसा भोथरा हो गया है कि अब काम नहीं करता है। मैं यह मानने वाला नहीं हूं कि बाढ़ एक दैविक दुर्घटना है। और जो बांध पिछले बर्षों में टूटे थे, आज भी टूटे हैं और भविष्य में भी टूटेंगे। इसमें मनुष्य का कोई चारा नहीं है। मेरा बिश्वास है कि मनुष्य की शक्तियां अपरिमित हैं और यदि ठीक ढंग से काम किया जाय तो कोई भी काम मनुष्य के लिए असंभव नहीं है और वह बड़ी से बड़ी बिपत्तियों पर काबू पा सकता है।

पंडित नेहरू ने कहा है :—"एनफ कैन बी डन टू फोरस्टाल दी कैलेमिटी एंड औबजर्ब इट्स शौक"। हम कहते हैं कि हमारे सिंचाई विभाग की शक्ति बाढ़ के पानी को रोकने की है, हम यह नहीं कहते हैं कि बाढ़ को पूर्ण रूप से रोका जा सकता था। हमारा यह कहना है कि इस कैलेमिटी को फोरस्टाल करने की शक्ति हमारे सरकारी बिभाग की कुंठित हो गई। पूर्ण रूप से बाढ़ को रोकना संभव न हो

लेकिन इसकी विभीषिका को कम कर सकते थे। हम समझते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके निकम्मापन से ऐसा हुआ। दूसरे देशों में इस तरह के निकम्मापन पर बहुत तरह की जांच हुआ करती है। यहां यही एक सदन है जहां हम इन सब बातों को कह सकते हैं। इस पर पंडित जी ने कहा है—

It seems that in China people were alerted and evacuated in time from the danger zone to a place of safety. Then there are reservoirs to which the floods are diverted. The floods thus lose much of their fury and velocity. China is a much harassed country as India is ; but there they have developed a way of fighting the calamity and robbing it of its destructive effects. There the engineers and laymen both combine.

हमारे नीतिश्वर बाबू ने कहा कि यहां लेमेन और इंजीनियरों के कम्बाइन करने की कौन सी बात आती है। हमारे क्षेत्र में रकठा नामका एक बांध था। जब लोगों को बांध के टूटने से क्षति हुई तो २½ मील की बांध खुद तैयार किया और जहां वाटरवेज और ग्रो-मोर-फुड का सारा बांध टूट गया वहीं बेगूसराय में भी जनता द्वारा निर्माणित बांध ज्यों का त्यों बना रहा जिसने गंडक के बाढ़ को आगे बढ़ने से रोका और गावों की रक्षा हो सकी मगर जहां लोगों को ऐसे काम के लिए उत्साह देना चाहिए वहां दफा १४४ जारी कर दिया गया। खैर ६० दिन खतम हो गया और मोकदमा भी खतम हो गया लेकिन उनकी परीशानी जो हुई वही उनको पुरस्कार मिला। मैं सिंचाई मंत्री जी से नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं दूसरे जगह के बारे में नहीं उनके अपने घर के पास की बात है वह बतायें कि फ्लड प्रोटेक्शन बांध के लिए जो टेंडर मांगा गया वह कब और काम कब आरम्भ किया गया। और क्या यह बात सही है कि एक-एक आदमी को तीन-तीन जगह काम दिया गया और वह भी ऐसे लोगों को जिनको इसका कोई तजरबा नहीं था और बिल्कुल नए थे और इस कारण काफी देर हुई? नौला तथा पड़ोसी गांव में हजारों-हजार आदमियों ने अपना श्रम दान दिया और २० हजार रुपया देकर बांध तैयार किया, लेकिन बांध टूटती है १ तारीख को और सैंकशन आता है ५ को। अगर वाटरवेज से थोड़ी सी मदद की गई होती तो इस बांध को बचाया गया होता मगर जहां बांध टूट जाती है वहां अपनी इन-एफीशियंसी को छिपाने के लिए हमारे सिंचाई बिभाग के लोग कहते हैं कि लोगों ने इसको काट दिया।

उपाध्यक्ष—शांति, शांति। थोड़ा समय है। आप जल्दी खतम करें।

श्री रामनारायण चौधरी: जहां इस रिपोर्ट में काजेज आफ फ्लड का जिक्र है, जहां उत्तर बिहार के जोगरफी का वर्णन है, जहां यह कहा गया है कि गंगा में सिल्ट उपस्थित होकर नदियों के मुंह पर रुकावट आ जाती है वहां एक और कारण जोड़ देना चाहिए :—

Interference with natural channels, railways and roads and bundhs constructed under unscientific, unmethodical and haphazard schemes under the auspices of Waterways and Grow More Food Irrigation schemes to appease local interest.

इसको जोड़ना जरूरी है। मैं लेकिन सिंचाई मंत्री का इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने दृढ़तापूर्वक माइनर इरिगेशन और ग्रो-मोर-फूड पर जो रुपया लुटाया जाता था उसको रोका ; अस्वाभाविक रूप से जो किसी को खुश करने के लिए बिना मेथड के बांध टूटने ही के लिए बनाया जाता उसको रोका गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक नक्शा दिया गया है। आलमनगर थाने के प्रतिनिधि ने कहा कि हमारा सारा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं है।

श्री विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल—आलम नगर का है।

श्री रामनारायण चौधरी—जी नहीं। तुनक लाल जी जब बोल रहे थे तो हमने देखा आलमनगर नहीं है। इस रिपोर्ट में एक बात वड़ी स्पष्टता से कही गई है :—

I coanfess, however, that investigation has not proceeded with the speed we desire or which the situation calls for.

यह एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा इंडोक्टमेंट है और सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में इस चीज को कबूल किया है। इससे बढ़कर इंडोक्टमेंट और क्या हो सकता है। हम इस स्पष्टवादिता के लिए प्रशंसा कर सकते हैं और हमारे केन्द्रीय मंत्री नंदा जी ने भी कहा है कि लैप्सेज हुए हैं। तो आपके एक्ट्स ओफ कमिशन एंड ओमिशन बाढ़ के विभीषिका को बढ़ाते हैं। युधिष्ठिर राजदंड धारण करने के समय यज्ञ करता था। आज के कलयुगी युधिष्ठिर ढोल देते हैं और दुर्योधन बनाकर बटवारे करते हैं। आज रिलीफ के बंटवारे की बात ये करते हैं। कंप्रिहेन्सन एंड एप्रिहेंसन की बात करते हैं।

उपाध्यक्ष—अब समय बहुत कम है।

श्री रामनारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक घटना का जिक्र मैं करना चाहता हूं। हमारे पास सबूत है। मुंहजबानी बात हम नहीं करेंगे। ३१ तारीख को बेगूसराय थाने के एक जवाबदेह आदमी ने जाकर लिखित आवेदन दिया एस० डी० ओ० के यहां कि हमारे गांव का बांध डूब गया और गांव भी डूब जायेगा आप रक्षा कोजिए। एस० डी० ओ० मोटर पर जाते हैं और उस आदमी को नोटिस देते हैं। एक दरखास्त देने पर क्या कार्रवाई होती है इसका नमूना मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं। "भोला राय, सा० बासुदेवपुर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी, बेगूसराय, चूंकि बजरिये नोटिस हाजा के आपको आगाह किया जाता है कि आप ता० ६ अगस्त, १६५४ को वजह दिखलावें कि क्यों नहीं आपके खिलाफ झूठे खबर देने के लिये कानूनी कार्रवाई की जाय" इसका क्या माने है। ३१ तारीख को यह वाकया है। आप किसको बाढ़ ग्रस्त कह सकते हैं। आपके अनुसार तो जहां पर कमरे भर पानी हो और हरएक आदमी के घर में पानी घुस गया और घर गिर गया हो। अगर यह परिभाषा बाढ़ पीड़ित इलाके को हो तो आपके और मेरे परिभाषा में अंतर है। इस तरह से खबर देने के लिये आपके अफसर कार्रवाई करने लगते हैं। बेगूसराय के आसपास के १० या १२ गांव तो एकदम दह बह गये हैं लेकिन तामी अभी तक कितने गांवों में रिलीफ पहुंच न पायी है। चेरिया गांव और पबरा गांव ऐसे ही गांवों में से हैं। हालत इस तरह की है और खबर देने पर मुकदमा शुरू हो जाय, यह कैसी बात है।

श्री रामचरित्र सिंह—हम खुद नौला गांव में गये थे और वहां पर रिलीफ बंट रही है।

श्री रामनारायण चौधरी—वह एक बड़ा गांव है और वहां आप जैसे बड़े-बड़े लोग रहते हैं और इसलिये वहां पर भले ही रिलीफ पहुंच जाय लेकिन बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक रिलीफ नहीं पहुंची है। लेकिन अभी भी मेरे जानते परज्ञा, मोहनपुर और बेगमपुर गांवों में रिलीफ नहीं पहुंची है। आप भी नौलागांव में २६ तारीख को गये थे और पटने से उस गांव तक जाने में आपको २६ दिन लगे हैं।

(इस समय अध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष—अब आपको खतम करना चाहिये। जो नियम बन जाय उसको सबको मानना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी—अच्छी बात है। जब आपका हुक्म हो गया तब मैं एक पद्य कह कर अपना भाषण खतम करता हूं:—

कहो जो चाहो सुन लेंगे मगर मुतलक न समझेंगे,
तबियत तो खुदा ने दी ही नहीं, कान हाजिर है।

डा० हबीबुर रहमान—जनाब सदर, आज दो दिन से............।

श्री रंग बहादुर प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक दरखास्त दी है और मैं यह जानना चाहता हूं कि उस पर क्या फैसला आपका हुआ।

अध्यक्ष—अभी तो हमलोग काम ही कर रहे हैं और आपको फैसला मालूम ही हो जायगा। अभी हमलोगों को बाढ़ के पानी होकर चलना है और धीरे-धीरे चल रहे हैं। इसलिये देरी होगी और इसलिये आपको फैसले के लिये घबड़ाना नहीं चाहिये।

डा० हबीबुर रहमान—जनाब सदर, मैं यह कह रहा था कि आज दो दिनों से सैलाब पर बहस हो रही है वह ऐसा सैलाब है कि जिसका मिसाल मिलना कठिन है। जितनी बर्बादी इस सैलाब के चलते हुई है उसका भी मिसाल नहीं मिल सकता है और जिसका ब्यान हमलोगों के जबान से बाहर है। उसे कलम की ताकत से लिखा भी नहीं सकता है। सरकार की तरफ से जो रिलीफ मिल रही है वह नाकाफी है और जितने मकान और फसल की बर्बादी हुई है उसको किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता है। इस वास्ते सरकार को यह इंतजाम करना चाहिये कि आगे चल कर इस तरह का वाक्या जिसमें नहीं हो और रिलीफ देने में जो खामियां हैं

उनको मैं आपके सामने और हाउस के सामने रख देना चाहता हूं। यह चीज सालो-साल की हो गयी है और इसके लिये सरकार को हर साल तैयार रहना चाहिये। सरकार को इस शैलाब को मुश्तकिल तरीके से रोकने के लिये भी उपाय करना चाहिये। अभी जो बाढ़ आयी है उसके संबन्ध में हमारे चीफ मिनिस्टिर की ओर से एक बयान हुआ है और उसमें यह दिखलाने की कोशिश की गयी है कि सरकार इसका मुकाबला करने के लिये मुस्तैद है। लेकिन मेरे जानते गुजास्ता बाढ़ के मौके पर सरकार की ओर से जो वादा किया गया था वह भी इस साल के बाढ़ के समय पूरा नहीं किया गया है। गुजास्ता बाढ़ के मौके पर सीतामढ़ी में काफी नाव रखने की बात थी लेकिन इस ओर कुछ भी नहीं किया गया और इसका नतीजा यह हुआ कि रिलीफ का काम भी ठीक से नहीं हो रहा है और सरकार को इस काम में नाकामयाबी हो रही है। हर साल अफसर भी बदल जाते हैं और जो अफसर आते हैं, नया होने से उनको पहले का तजरबा भी नहीं होता है। उस सबडिवीजन के पुपरी थाना जहां से मैं आया हूं और उसकी आबादी करीब २½ लाख की है और मुश्किल से २५ या ३० हजार की आबादी इस बर्बादी से बची होगी। वहां पर अभी सिर्फ १५ नावें हैं और आप समझ सकते हैं कि इतनी नावों से रिलीफ का काम किस तरह से इतनी बड़ी आबादी में हो सकता है और नावों की कमी से रिलीफ का सामान भी बहुत जगहों में अभी पहुंच नहीं पाया है।

स्टेटमेंट में मुख्य मंत्री साहब ने बाढ़ को रोकने के लिए जो कार्रवाई करने का वादा किया है उसमें कोशी के पश्चिम और चम्पारण जिले से लेकर मुजफ्फरपुर और दरभंगा को भी शामिल करना चाहिए। अधवारा के संबन्ध में केन्द्रीय सरकार ने जो स्कीम मंजूर की है उसको भी अमल में लाना चाहिए। अगर उन नदियों को खोदकर उसके दोनों किनारे पर बांध बांध दिया जाय और नदी को नाले से इन्टर कनेक्ट कर दिया जाय तो सिंचाई का काम बहुत ठीक होगा। पानी भी बाहर नहीं निकल सकेगा। बागमती और लखनदेई नदी को भी ट्रेन करने की जरूरत है ताकि बाढ़ के जमाने में पानी बाहर न जा सके और मुसीबत का सामना न करना पड़े। इन स्कीमों को अमल में लाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट खोला जाय जैसा कि अकाल के जमाने में पूर्त्ति विभाग खोला गया था। ठीक उसी तरह एक बाढ़ नियंत्रण विभाग खोला जाय और एक बाढ़ नियंत्रण कमिश्नर मुकर्रर किये जायं जो साल भर काम करते रहेंगे।

ग्रैचूटस रिलीफ के बारे में मुझे दो बात कहनी है। यह रिलीफ बे जमीन वाले मजदूर को दी जाती है। बाढ़ के जमाने में जमीन बेकार हो जाती है और छोटे-छोटे किसान जिनकी जिन्दगी इससे बसर होती है वे भी तो बे जमीन हो जाते हैं और करीब-करीब बेकार हो जाते हैं। इसलिए सरकार से मेरा अर्ज है कि इन किसानों को भी ग्रैचूटस रिलीफ देकर मदद करनी चाहिए।

इसके बाद मुझे एपिडेमिक के बारे में यह कहना है कि सरकार का जो इंतजाम है उसमें मुस्तैदी की जरूरत है। एपिडेमिक से दूर रहने के लिए पीने का पानी का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि हर देहात में कम से कम एक ट्यूब-वेल बना देने से एपिडेमिक रुक सकता है।

आखिर में इस्तदुआ करूंगा कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जितना वादा किया गया है उसे बाढ़ के बाद फौरन अमल में लाया जाय ताकि आइन्दे पब्लिक को राहत मिले और उम्मीद बंध सके। उत्तर बिहार के लिये शैलाब कोई नई बात नहीं

हैं इसके वास्ते सरकार को कवल से रोक थाम करने का उपाय करना चाहिये और यह कहना कि बाढ़ बहुत कवल और अचानक आ गई मुनासिब नहीं है। बल्कि अगर कहा जाय कि उसने गफलत से काम लिया है तो वाजिब होगा।

श्री जनक सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार वर्षों से बाढ़ से पीड़ित होता आ रहा है, लेकिन इस बाढ़ ने जो भीषण स्थिति पैदा कर दी है वह अवर्णनीय है। सदन के सदस्यों ने इसकी भीषणता पर जो प्रकाश डाला है उसके संबन्ध में दो मत नहीं हो सकता है। इस बाढ़ से करोड़ों रुपये की फसल बर्बाद हो गयी है। इसकी चर्चा मुख्य मंत्री ने भी अपने स्टेटमेंट में की है। लाखों आदमी इसके चपेट में आ गए हैं, हजारों परिवार बेघर हुए हैं, सैकड़ों आदमी काल के कराल गाल में चले गये। हजारों मवेशियां पानी में बह गये जिसकी गणना सरकार की ओर से भी नहीं हो पायी।

अध्यक्ष महोदय, अगम अथाह जलराशि से परिप्लावित उत्तर बिहार के उस बड़े भूभाग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं जहां के लाखों प्राणी हाथो पानी मचान पर या सड़कों पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। दुःख का दिन काट रहे हैं। उनका मुख मंडल उनके दुर्दिन का साक्ष्य देता है, इजहार करता है। अब मैं सरकारी सहायता की ओर आपका ध्यान खिंचना चाहता हूं। सरकार की ओर से सहायता तो जरूर दी जा रही है, मगर परिस्थिति के अनुसार वह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं होता कि सरकार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार मदद करने में सचेष्ट है। एक चीज की कमी सरकार को हमेशे रही है और वह है समय की सुझ। मुजफ्फरपुर सबडिवीजनल बाढ़ एडवाइजरी कमिटी ने बाढ़ आने के एक माह पहले यह विचार प्रकट किया था कि आने वाली बाढ़ से सामना करने के लिए सरकार को काफी नाव का इंतजाम करना चाहिए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस विचार पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और बाढ़ आने के बाद जब नाव की मांग होने लगी तो नाव का पता तक नहीं था। इस वक्त नाव बनाने के लिए सरकार को जितना पैसा खर्च करना पड़ता है उतने ही पैसे में आज की अपेक्षा दो गुणा नाव बन सकती थी। यदि इस काम को बाढ़ आने के पहले किया जाता। इसलिए मुझे यह कहने में हिचकिचाहट नहीं होती है कि इस संबन्ध में सरकार सुस्ती से काम लिया है।

मैं यह बिना संकोच कह सकता हूं कि अंग्रेजों के समय जिस तरह उत्तर बिहार उपेक्षित था ठीक उसी तरह से आज भी उपेक्षित है। बाढ़ आने के बाद बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान सोचा जाता है लेकिन इससे क्या समस्या का समाधान हो सकता है? गत वर्ष बाढ़ के अवसर पर केन्द्र से पंडित नेहरू तक दौड़ पड़े थे। समस्या के समाधान के लिये केन्द्र ने तीन लाख रुपया भी दिया लेकिन दुःख है कि इन क्षेत्रों के जांच का काम इस वर्ष बाढ़ आने के दश दिन पहले से प्रारंभ हुआ है। अगर सरकार यह समझ रखा है कि कोशी योजना को कार्यान्वित कर देने से ही उत्तर बिहार की सारी समस्यायें हल हो जायंगी तो मैं समझता हूं कि यह खयाल गलत है। बागमती, बुढ़ी गंडक, लखनदेई और सिकरना नदी को पालतु बनाना बहुत जरूरी है। इन छोटी-छोटी नदियों को पालतु बनाकर ही उत्तर बिहार को सस्यश्यामला बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय; आज जो स्थिति इस प्रांत की है और जो वक्तव्य मुख्य मंत्री का है उससे पता चलता है कि ४ वर्षों के अन्दर करीब १७० करोड़ रुपये की वरबादी किसानों की हुई है। जिस राज्य का १७० करोड़ रुपया इस तरह नष्ट हो जाय, १६ करोड़ रिलीफ रूपी पूर्णाहुति में हवन हो जाय उस राज्य को क्या हाल होगा। अध्यक्ष महोदय, आज भी अतिवृष्टि और अनावृष्टि की समां राज्य के सामने उपस्थित है। मैं समझता हूं कि इस तरह की समां बराबर उपस्थित होती रहीं तो सरकार के सामने एक बहुत बड़ी मुसिवत होगी और इस तरह की सरकार ज्यादा दिनों तक टिकने में अपने को असमर्थ पायगी।

अध्यक्ष महोदय, इन सभी समस्याओं के समाधान के सिलसिले में मैं कुछ सुझाव आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं। सबसे पहले मेरा ख्याल है कि--

(१) वागमती, बूढ़ी गंडक, लखनदेई तथा कमलादि नदियों की जांच-पड़ताल करने के लिए तथा नियंत्रण के लिए केन्द्रीय कमीशन के साथ-साथ एक प्रांतीय कमीशन की भी नियुक्ति हो।

(२) प्रांतीय कमीशन को निश्चित अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट उपस्थित करने का आदेश हो।

(३) बाढ़ से जो गांव प्रतिवर्ष आक्रांत रहते हैं उनकी सूची सरकार तैयार करावे और बाढ़ के अवसर पर जिन-जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन चीजों का इंतजाम बाढ़ आने के पहले ही किया जाय।

(४) बाढ़ के समय पेय जल की कमी रहती है इसलिए नलकूप का प्रवन्ध हर पीड़ित गांवों में हो।

(५) २० पीड़ित गांवों के बीच एक औषधालय का निर्माण हो।

(६) प्रतिवर्ष बाढ़ से पीड़ित होने वाले किसानों को विना सूद के रुपये दिए जाएं। किस्त भी लम्बी हो।

(७) १०-२० रुपये जो घर वनाने के लिए मजदूरों को सरकार की ओर से हर साल दिये जाते हैं और हर साल वे घर दह जाते हैं वहां के संबन्ध में मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार वहां ऊंची जगह चूने और मजदूरों के लिए घर बनवाए जिसमें आधा रुपया सरकार लगाए और आधा रुपया मजदूरों की मजदूरी एवं उन से संबंध रखने वाले किसानों से लिए जाएं।

अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया। अब आप वैठ जाएं।

---

श्री जनक सिंह—इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

---

श्री बसावन सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने बाढ़ के ऊपर जो वक्तव्य दिया है और इस विषय पर बात करने का जो मौका मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

स्टेटमेंट को जांच करने पर उसमें कई बातें तो काम की मिली हैं और कई बातें, चूंकि स्टेटमेंट देना है, इसलिए दे दी गयी हैं। मैं इसके प्रकोप की समालोचना में नही जाना चाहता हूं लेकिन इंजीनियरिंग की जो बहस हुई है इस वक्त बिल्कुल असंगत है और कई पन्ने उसमें लगे हैं। इंजीनियरिंग का तो सवाल यह है कि जो

कुछ हमारी सरकार ने पिछले कई वर्षों में किया उससे कोई नतीजा नहीं निकला है और न उनका आखरी निश्चय निकला। वह भी तय नहीं होता है। एक साहब एक प्रस्ताव देते हैं और फिर दूसरे साहब उसको गलत बता देते हैं। दो-तीन साल के बाद तीसरा प्रस्ताव आता है, यह बात है। जहां तक नदियों के नियंत्रण की बात है, कुछ दिन स्ट्रेस रहता है कि वेस्टर्न तरीके से उसको कंट्रोल में लावें, या चाइने तरीके से उसको कंट्रोल में लावें या फौजी तरीके से उसको कंट्रोल में लावें। हम समझते हैं कि बिल्कुल बेकार है, इस तरह की बहस से। चाइना तरीके की बात कहते हैं, चाइना में यल्लो रीवर को बांध से बांधा गया। वहां ह्वांगहो कोसी से सौ गुना सिल्ट लाती है और उसकी वैलोसीटी भी ज्यादा है, उसमें जितने मैकेनाइज तरीके से काम हो रहा है हमारे देश के किसी भी रीवर वैली स्कीम में नहीं है। सवाल यह है कि नदी की प्रकृति क्या है, किस तरह बांध बनाया जा सकता है यह देखना है। अभी एक इंजीनियर से बातचीत हुई, बातचीत ही नहीं हुई बल्कि बहस भी हुई। उन्होंने कहा कि ८० दिन में बांध बना दिया जा सकता है। ८० दिन या १०० दिन की बात नहीं है। देखना यह है कि बेगैर यूकलीड का होगा या नहीं, बेगैर हेवी मेशिनरी के होगा या नहीं। वह इंजीनियरिंग सवाल है। कितने मेशिनरी लगावें, कितने आदमी लगावें। अभी भकरा नंगल में देखा होगा उसमें ज्यादा हाथ से काम हो रहा है। जहां तक लोगों को ड्राफ्ट कर लाने का काम है १० लाख आदमी काम करते हैं। यह भी सोचना होगा कि इतने आदमी ड्राफ्ट किया जा सकता है या नहीं। एक गांव से दूसरे गांव में आदमी बिना पुलिस के परमिट के नहीं जाते हैं। सरकार जो कुछ बतायगी वह करना होगा वरना जिन्दगी से बाजदावा देना होगा। क्या आप यह कर सकते हैं? दूसरा इन्सेंटिव क्या है सिर्फ तनख्वाह पाने का। आपकी जिन्दगी में जो फासला है जब तक यह नहीं हटता तब तक इंजीनियरिंग के हिसाब पर मुनहसर रहना होगा और साधन जुटाना होगा कि मेशिन से आदमी को कहां तक समन्वय कर सकते हैं। बाढ़ कोई नई चीज नहीं है बाढ़ इस इलाके में आती है, इसकी भीषणता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और परेशानी भी बढ़ती जाती है। हमलोग ले मैन हैं, इंजीनियर नहीं हैं, ज्यादा जानते नहीं हैं जब तकलीफ होती है तो मूंह से बात निकलने लगती है। हमें यह समझना है कि बांध बांधने का जो सवाल है, पोपुलर एफर्ट से वह ऐसा न बने कि उससे बाढ़ की भीषणता और बढ़ जाय। कर्पूरी जी ने कहा है कि एक्सटेंशन सर्विस के, कम्युनिटी प्रोजेक्ट और माइनर इरीगेशन के जरिए काम होता है। इस तरह का जो काम है वह बन्द कर दिया जाय और जो कच्चा होता है उससे पक्का काम कराया जाय। अभी तो मुख्य मंत्री ने कहा है कि कोसी सिसटम को हम ठीक कर लेंगे और अधवारा सिसटम को भी ठीक करने की बात है। गंडक बांध बनाने का प्रोमिस दूसरे पंचवर्षीय योजना में है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि ५-१० या १२ साल जो कुछ भी लगे १२ साल हम क्या करें। १२ साल हमें उसी तरह रहने दिया जाय या बाढ़ आवे तो इंजीनियरिंग की बहस करें और बाढ़ खत्म हो जाय तो इंजीनियर को भूल जाय। इसके लिए रिलीफ की माकूल व्यवस्था होनी चाहिए और आदमियों को बचाना चाहिए। जब-जब बाढ़ आती है तो हमारे दिमाग में भी बड़ी परेशानी आती है। हमारे दिमाग में यह बात आती है कि उनको वहां से माइग्रेट क्यों नहीं करते हैं। माइग्रेशन का सवाल और भी बीहड़ है। वे कहां जायगें, कहां रहेंगे यह बड़ा सवाल हो जाता है और रोग से उसका जो निदान है वह ज्यादा भयंकर हो जाता है। इसका क्या इलाज निकालें यह सोचना है। जो सरकारी अफसरों ने काम किया वह जरूर तारीफ के लायक है और हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। लेकिन किया क्या है।

उनके हाथ में क्या साधन दिया है। बाढ़ के रोकने का सवाल है तो क्या कोई उसको रोक सकता है। लेकिन जब बाढ़ आवे तो नाव की मुकमल व्यवस्था होनी चाहिए और जो नाव हों उनको बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में देना चाहिए। ६ महीने तक सुखा रहता है इसका इन्तजाम करना चाहिए और अनुमान लगाना चाहिए कि कितने नाव की जरूरत होगी।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—नयी जगह में भी बाढ़ आ जाती है।

श्री बसावन सिंह—अगर आप २०,००० नाव का प्रबन्ध करते हैं और उसमें से अगर २,००० नयी जगहों में भेज दें तो पुरानी जगहों के लिए १८,००० से काम चल सकता है। नाव की कमी होने से जलावन तक लोग नहीं ला सकते हैं। यह काम आप कर सकते थे। खैर दवादारू का आफ्टर इफेक्ट जो बाढ़ का है आप उससे मवेशियों को बचाने का कोई उपाय नहीं करते हैं। न कोई इलाज करते हैं। आदमियों के पानी पीने के लिये पाईप लगाया गया है। एक हजार पाईप लगाया गया। पर उससे कोई फायदा नहीं। सारा पानी विषाक्त हो गया है और लोगों को डिसैन्ट्री और हैजा हो गया है। इस काम के लिये स्वतंत्र मंत्रिमंडल बनाना चाहिये और एक स्वतंत्र मंत्री इस काम के लिये रहें। उनका एक डिपार्टमेंट रहे। वह हमेशा ध्यान रखें कि कब हिमालय पर पानी पड़ता है और कब उधर से पानी आता है। फिर आप काम कर सकते हैं। मेरा निश्चित मत है कि इसके लिये आप ऐसे आदमी को चुनें जो सबसे ज्यादा मेहनती और कल्पना वाला आदमी हो जो ड्राइव दे सकता है। वाकी कामों को छोड़ इनके जिम्मे यही एक काम रहना चाहिये। वह बाढ़ कमीशन का काम है और रिसर्च के लिये उनके जिम्मे सारा काम सौंपा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अखबार में समालोचना होती है कि २६ या २७ जुलाई को बाढ़ की खबर आती है और सरकार १६ तारीख तक रांची ही में पड़ी रहती है।

एक सदस्य—मैं जानना चाहता हूं कि सरकार रांची में पड़ी रहे तो काम नहीं हो सकता है?

श्री बसावन सिंह—इतनी अच्छी तरह से नहीं हो सकता है जितना पटने में रहने से। हमारी राय है कि जब पटने में सरकार रहती है तो तत्परता से काम हो सकता था और लोगों को राहत पहले मिल सकता था। आपने कहा कि दवा वगैरह का इंतजाम कर लें। हम समझते हैं कि दवा पहुंचते-पहुंचते तथा इलाज होते-होते बात बहुत बिगड़ जायेगी। मैं समझता हूं कि रिलीफ देने के काम में, रिहैबिलिटेशन के काम में जो पैसे का इंतजाम है वह नाकाफी है। मैं आप से कहता हूं कि पिछले समय जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो २६ रु० मन चावल बिकता था और बाद में बंगाल में १३ रु० मन चावल बिका है। चावल जो कम दाम में बिका वह सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से। बंगाल जो कि सरहद पर पड़ता है वहां की सरकार स्टेबूल नहीं है, भरोसा नहीं रहता कि आगे क्या होगा। इसलिये सेन्ट्रर की निगाह वहां बराबर रहती है परन्तु बिहार के लोग क्या इतने अयोग्य हैं कि वहां से सहायता नहीं मिलती। मद्रास में राजा जी ने आवाज उठाई कि हैंडलूम लेबरर्स बहुत अफेक्टेड हैं, स्ट्रीकेन हैं तो उसी दिन से काटेज इंडस्ट्रीज की बनी हुई धोती और साड़ी की

(बना हुआ) लोगों को खरीदने के लिये कहा गया। भारत सरकार ने १० करोड़ रु० की मदद की। बिहार राज्य में रिलीफ के लिये सेन्टर से सहायता नहीं मिलेगी तो कहां से मिलेगी। बिहार को जो कुछ भी मदद मिलती है वह सेन्टर के शेयर से पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी बिपत्ति में केन्द्र से मदद नहीं मिल पाता तो क्या मतलब हुआ एक देश में रहने का। क्या हमारी आवाज में इतनी ताकत नहीं है कि वहां तक पहुंच सकें। मकान बनाने के लिये या लोगों को बसाने के लिये जितने रुपये की आवश्यकता है उतने होने चाहिये। यह तो नहीं कि दस-बीस मकान बना देते हैं और कहते हैं कि अब नहीं बना सकते। आपने कहा है कि ५० करोड़ का घाटा हुआ है, ६०-७० करोड़ का हुआ है। यह आपने कबूल किया है कि दुबारा जो बाढ़ आई है उसमें ८५ करोड़ का घाटा हुआ है। अब सवाल यह है कि रब्बी की खेती नहीं हुई तो लोग खायेंगे क्या।

चारो ओर से पानी ड्रेन आउट करके रब्बी की फसल को बोने का उपाय करना चाहिये। यह काम किसान नहीं कर सकते हैं, यह तो सरकार ही कर सकती है। मशीन को लाकर पानी को पम्प आउट किया जा सकता है। सूबे के जितने ट्रैक्टर हैं उनको लाकर जुताई के काम में मदद देनी चाहिये। अगर वहां के आदमी काम नहीं कर सकते हैं तो दिक्कत और बढ़ जायगी। एक सलाह और है कि शौर्ट क्रौप जैसे मड़ुवा वगैरह को बोने का इंतजाम सरकार करे। सुगर फैक्ट्री के मजदूरों को मिल मालिकों ने रिलीफ में मदद के लिये एक महीने की तनख्वाह दी है और वे एक ही बार अदा करना चाहते हैं। इसी तरह रेलवे ने भी अपने कर्मचारियों को जो बाढ़ से पीड़ित हैं उनको रिलीफ के लिये रुपये दिये हैं लेकिन वे ३ रुपया माहवारी अदा करेंगे। आप मिल मालिकों को यह कह सकते हैं कि आप भी रेलवे की तरह इन मजदूरों से तीन या पांच रुपये माहवारी अदा करें नहीं तो उनकी दिक्कतें कम नहीं होंगी। तकावी और मालगुजारी के वसूलने का जहां तक सवाल है मैं भी आपलोगों से सहमत हूं कि यह माफ होनी चाहिये। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पर विचार करेंगे और संभव हो तो मंजूर भी करें।

श्री रामेश्वर प्रसाद यादव—अध्यक्ष महोदय, बिहार में बाढ़ की समस्या पर बहुत कुछ कहा जा चुका है लेकिन मैं थोड़े से शब्दों में कुछ कहना चाहता हूं जो सरकार से अभी भी पूरा नहीं हो सका है। बाढ़ की समस्या पर गत साल भी सदन में चर्चा हुई थी। लेकिन आज देहातों में बाढ़ के आने पर कितने आदमी बिना नाव के बह गये और नाव का इन्तजाम पूरा नहीं हो सका। इस साल २६, २७ जुलाई को बाढ़ आ गयी लेकिन नाव का पूरा इंतजाम नहीं हो सका। दूसरी बार फिर २२ से २५ अगस्त तक बाढ़ आ गयी उसमें भी नाव का जैसा इंतजाम चाहिये वैसा नहीं हो सका है। रिलीफ की बात तो अलग है। इसकी कमी के कारण सरकारी कर्मचारी देहातों में नहीं जा सकें यह देखने के लिये कि वहां कौन आदमी डूब रहा है। सरकार का जैसा रवैया है वह बाढ़ को नहीं रोक सकती है। कोसी एरिया की बात हम पहले सुनते थे लेकिन इस बार तो हमें साक्षात यह देखने को मिला। सीतामढ़ी सबडिवीजन में लखनदेई नदी का बड़ा प्रकोप रहा। जब सरकार बाढ़ को नहीं रोक सकती है तो कम से कम वह नाव का इंतजाम करने में समर्थ है और यह काम होना चाहिये। जब गांवों में और शहरों में पानी घुस जाता है तब कहीं नाव का इंतजाम होता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि हर थाने में हर सबडिवीजन में और जिला में यह देखे कि कहां कितनी नाव की जरूरत है और उसका

इंतजाम अभी से कर दे। खैरात का जो इंतजाम है वह समुचित नहीं है। छोटे-छोटे किसान जो दुबारे खेती किये और वह भी वह गयी इसलिये अब उनके पास कोई साधन और समय भी नहीं है कि तीसरी बार खेती करें। एक बात और है। तकावी ५ आदमियों को मिलाकर दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि जब तीन आदमियों के पास पैसा होता है और वे देना चाहते हैं तब दो आदमी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिये आप कानून में सुधार करें ताकि जब ५ आदमियों को मिलाकर तकावी दिया जाता है तब एक आदमी को अकेले क्यों नहीं दिया जा सकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जमींदार हैं वे बकाश्त जमीन जोतते हैं और जिनके पास बकाश्त जमीन नहीं है वे जीरात जमीन जोतते हैं। वे लोग जब तकाबी लोन लेने जाते हैं तो उनको एस० डी० ओ० के यहां दरखास्त देनी पड़ती है और रजिस्ट्रार जांच करता है। इस तरह उनको लोन लेने में काफी दिन लग जाते हैं और उनको समय पर लोन नहीं मिलता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द उन लोगों को भी लोन मिल जाया करे।

तीसरी बात देहातों में फेयर प्राइस शौप खोलने की है। सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि सस्ते दुकान खोले जायं। लेकिन अभी तक दुकान नहीं खुल सकी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष—मुझे मालूम हुआ है कि बहुत से माननीय सदस्य इस वादविवाद में भाग लेना चाहते हैं। इस लिए मैं घोषित करता हूं कि यह वादविवाद आज समाप्त नहीं हो रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि १४ ता० को फिर यह वादविवाद लिया जायगा। वादविवाद के समय की सूचना दी जायेगी।

सभा सोमवार, तिथि १३ सितम्बर, १९५४ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

रघुनाथ प्रसाद,
सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना, तिथि ३ सितम्बर, १९५४।

बि० रा० मु० (ए एल० ए०) २०७—मोनो—७९४+१—७-१-१९५५—शी०प्र०सिंह